mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-06 अंक-174 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
25 जून 2026 गुरुवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

दैनिक मीडिया ऑडिटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

बुजुर्गों की सेहत पर भारी पड़ रही लापरवाही

भारत में हर साल फ्लू से 1.2 लाख मौतें, टीका लेने वाले 2% भी नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 'जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ गेरियाट्रिक्स' में छपे विशेषज्ञों के एक नए अध्ययन के अनुसार, देश में हर साल इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के कारण लगभग 1.2 लाख लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें करीब दो-तिहाई लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते हैं। इसके बाद भी देश के 2% बुजुर्गों ने भी फ्लू से बचाव का टीका नहीं लगवाया है।

समझिए क्या कहते हैं आंकड़े?

रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने 'लोंगीट्यूडल एजिंग स्टडी इन इंडिया' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बुजुर्गों में टीकाकरण की स्थिति बेहद दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिकटिटनेस-डिप्टीरिया का टीका सिर्फ 2.75% बुजुर्गों ने लगवाया है।

हेपेटाइटिस बी का टीका केवल 1.82% लोगों को मिला है। इन्फ्लूएंजा (फ्लू) की वैक्सीन महज 1.59% बुजुर्गों तक पहुंची है। इतना ही नहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि निमोनिया से बचाने वाला न्यूमोकोकल वैक्सीन तो सिर्फ 0.74% लोगों ने ही लिया है।

भारत में बुजुर्गों का टीकाकरण

ना के बराबर: इस मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सुरनजीत चटर्जी का कहना है कि भारत में वयस्कों और बुजुर्गों का टीकाकरण न के बराबर है, जिसमें तुरंत सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना सेहत में एक निवेश की तरह है। यह बुजुर्गों को संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत से बचाता है। इसके लिए कई सरकारी और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।

निमोनिया का खतरा सबसे ज्यादा: रिपोर्ट में जहां एक तरफ इस बात पर जोर दिया गया है कि निमोनिया का टीकाकरण सबसे कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बुजुर्गों के अस्पताल में भर्ती होने की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है, जिसमें निमोनिया सबसे आम है। इसके बाद भी 1% से कम बुजुर्गों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन ली है।

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में हर साल खतरनाक न्यूमोकोकल बीमारी से 6 से 8 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग या पहले से बीमार लोग शामिल हैं।

क्यों आ रही है यह नौबत?

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉ. सनी सिंघल और एम्स दिल्ली, जिपमेर पुडुचेरी व सीएमसी वेलोर जैसे बड़े संस्थानों के डॉक्टरों की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उनके अनुसार, इस लापरवाही की मुख्य वजहें हैं कि भारत में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए कोई एक तय राष्ट्रीय गाइडलाइन नहीं है। इसके साथ लोगों में जागरूकता की भारी कमी है और टीकों को लेकर लोगों में हिचकिचाहट, वैक्सीन की कीमत और आम लोगों तक इसकी आसान पहुंच न होना भी बड़ी बाधा के तौर पर है।

: ब्रीफ बॉक्स :

गंगा नदी में नाव पर बैठकर बीयर पार्टी नॉनवेज खाया

वाराणसी,एजेंसी। काशी में गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज और बियर-शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। वीडियो में 5 नाविक नाव में बैठकर चिकन बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शराब और बियर भी पी रहे हैं। इसके बाद वह नॉनवेज भी परोसते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद दशाश्वमेध चौकी प्रभारी ने मंगलवार को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने BNS की धारा-196 और धारा-299 के तहत केस दर्ज कर 5 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया। नाव को सीज कर दिया है। हालांकि, वीडियो कब का है? इसकी जांच की जा रही है।

मंगलवार को पुलिस सभी को कोर्ट में पेश करेगी। जुर्म साबित होने पर आरोपियों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। मामला दशाश्वमेध थाना क्षेत्र का है। एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया- पांचों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

सरकार बोली- एथेनॉल फ्यूल में चीटियां लगने का वीडियो फेक

पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने की बात गलत

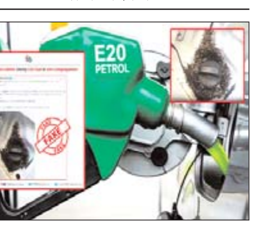

नई दिल्ली,एजेंसी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पूरी तरह से साइंटिफिक है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वाहन के फ्यूल टैंक के पास चींटियां दिखाई गई थीं। इस पर भारत पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईंधन ग्रेड एथेनॉल में कोई शर्करा (चीनी) नहीं होती।

मंत्रालय के अनुसार, कुछ लोग पुराने वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर कर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। सरकार ने कहा कि श्व20 पेट्रोल डालने के बाद इंजन खराब होने की कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।

ई20 पेट्रोल से वाहन बीमा पर कोई असर नहीं: केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल फ्लेक्स ईंधन) के इस्तेमाल से वाहन बीमा (इंश्योरेंस) की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

इस तरह की आशंकाएं गलत हैं और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद इन्हें खारिज कर दिया गया है।

हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड

शिमला,एजेंसी। किन्नौर जिला के निचार में आज सुबह तड़के चार बजे बादल फटने के बाद कुछ देर तक भारी बारिश हुई। इसके बाद काचरंग नाला में फ्लैश फ्लड आ गया। डीसी किन्नौर अमित शर्मा ने बताया कि इससे किसी प्रकार के जान व माल को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ग्रामीणों का रास्ता फ्लैश फ्लड में जरूर बह गया। वहीं शिमला में भी अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई है। सुबह 10.30 बजे मौसम साफ रहा और हल्की धूप खिली रही। मगर 11 बजे बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन जारी कर दोपहर तीन बजे तक शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

मुंबई में बारिश से पेड़ उखड़े, कई गाड़ियां दबीं

» अगले 3 दिनों में एमपी-यूपी पहुंचेगा मानसून

अंधेरी सब-वे बंद, लोकल ट्रेन सर्विस भी बाधित

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना,एजेंसी। मानसून की मुंबई में एंट्री के पहले 24 घंटे में ही लोगों की परेशानी बढ़ गई। मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 7 बजे तक दो इलाकों मलवणी फायर स्टेशन में 334द्धद्ध और एफ/साउथ वार्ड में 328एमएम बारिश हुई है। इसके अलावा 27 इलाकों में 200एमएम से 300एमएम के बीच बारिश हुई।

मुंबई में अंधेरी सब-वे में पानी भर गया। इसे अस्थाई रूप से बंद किया गया है। विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रिटेनिंग वॉल गिर गई। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, जिसकी चपेट में आने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने आज मुंबई और पालघर में बारिश का रेड और ठाणे-रायगढ़-सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर, देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री-मानसून बारिश जारी है। म.प्र. के 17 जिलों में मंगलवार को प्री-मानसून बारिश रही। मंगलवार को बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई।

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पहुंच सकता है।

7 राज्यों में गर्मी का असर, पारा 40डिग्री पार... मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और गुजरात के कई शहरों में बुधवार को पारा 40एष्ट से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के बांदा में 43.3डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बिहार के बौधगया में 40.8डिग्री, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में 40.8डिग्री, झारखंड के डाल्टनगंज में 41.2डिग्री, गुजरात के राजकोट में 40.5डिग्री और एमपी के खजुराहो 40.4डिग्री रहा।

दिल्ली में बच्ची से रेप-हत्या आरोपी को गोली मारी

» पुलिस का दावा- भागने की कोशिश कर रहा था

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में 11 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या का आरोपी मंगलवार रात पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि उसे क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। रोकने के लिए उसे पैर में गोली मार दी गई। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है।

पीड़ित बच्ची गुब्बारा बेचती थी। सोमवार सुबह फुटपाथ पर सो रही थी। आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर बबलू ने उसे अगवा किया। उसका रेप किया और हत्या कर लाश महरौली के जंगल में फेंक दी।

सोमवार सुबह करीब 6 बजे परिवार ने PCR कॉल के जरिए महरौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज और मुखबिर की मदद से चार घंटे में ही बबलू को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया। पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

नींद में बच्ची को उठाया, जंगल में ले गया... आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सड़क से गुजरते समय उसने सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर बच्ची को सोते हुए देखा था। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर महरौली के जंगलों में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया।

पुणे मर्डर: मंगेतर के साथ सिया की रोमांटिक पोस्ट

» गर्मी में हुडी पहनने से हत्या का खुलासा

प्रेमी लोहगढ़ किले पर दोनों के पीछे-पीछे आया

पुणे,एजेंसी। पुणे में मंगेतर की हत्या करने वाली 20 साल की सिया गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल (26) के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने के वीडियो।

दोनों की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थीं। इस साल फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को उसका घर मिले एक महीना पूरा हुआ। उसने केतन को टैग भी किया था।

पुलिस के मुताबिक, 18 जून को केतन की मौत के दिन लोहगढ़ किले पर एक युवक 33एष्ट तापमान में हुडी पहनकर आया था। पुलिस ने जांच में इसे ही आधार बनाकर एक-एक कड़ियां जोड़ीं। आखिरकार सिया और उसे बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22) को केतन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।

सोशल मीडिया पर सिया और उसके मंगेतर केतन का रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसी थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था। केतन ने एक महीने पहले यानी 19 मई से ही काउंटडाउन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। वह रोज उसे अलग-अलग तरीके से अपनी मंगेतर सरप्राइज देता।

सिया सोशल मीडिया पर इसके वीडियो पोस्ट करती थी। ये पोस्ट अब वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट देता दिखा।

कॉकरोच पार्टी फाउंडर दीपके बोले- हम आतंकवादी नहीं

» प्रधान ने सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार चौथे दिन अपना धरना-प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दहशतगर्दों की बी टीम वाले बयान का जवाब दिया। दीपके ने कहा, 'सोचिए प्रधान ने क्या कहा। जब हम उन छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि CJP आतंकवादियों की बी टीम है। अभिजीत ने कहा-

शिक्षा मंत्री देश के युवाओं को आतंकवादी कह रहे हैं। सर, हम आतंकवादी नहीं हैं। हमें आप जैसे लोगों से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

इसके बाद एक्स पर एक और पोस्ट में दीपके ने लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कहते हैं। विडंबना यह है कि उनके हाथ 17 से ज्यादा छात्रों के खून से रंगे हैं।'

शिक्षामंत्री के हाथ छात्रों के खून से रंगे

शिक्षा मंत्री बोले थे: जिन्हें डेमोक्रेसी ने रिजेक्ट किया, वे भेष बदलकर वापस आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ह्रष्ठञ्ज को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था, वे भेष बदलकर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है। प्रधान ने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर शिक्षा को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हों या फिर शिक्षा माफिया हों, इन पर नजर रखी जा रही है। हम इन्हें घुटने पर लाएंगे, नहीं तो हम देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते।

पंजाब सीएम वायरल वीडियो विवाद में 3 नए खुलासे

फाइव स्टार होटल में सीक्रेट मीटिंग, सीपी-एसपी के रूम बिल

लुधियाना/ चंडीगढ़/ गुरुग्राम, एजेंसी। पंजाब सीएम भगवंत मान से जोड़े जा रहे विवादित वायरल वीडियो को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। हरियाणा के फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया कि पंजाब के बड़े अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित फाइव स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग कर फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई।

इसमें वीडियो को डीपफेक बताने के लिए कहा गया। 16 जून 2026 को हुई इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।

इसके अलावा, एसपी जश्न गिल पंजाब के नाम से मोबाइल में सेव एक नंबर की व्हाट्सऐप चैट भी सामने आई है। इसमें सीएम की वीडियो रिपोर्ट में बदलाव को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि इसी बीच लुधियाना के पुलिस कमिश्नर डीआईजी स्वपन शर्मा और एसपी जशनदीप सिंह के गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में ठहरने के बिल भी सामने आए हैं।

इस मामले में मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस 2 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर चुकी है। शिकायतकर्ता और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पंजाब पुलिस के 2 अफसरों ने गुरुग्राम के होटल क्राउन प्लाजा में उससे 10 लाख रुपए में डील की थी। उसके माध्यम से साइबर यान और सिफर सेंटिनल लैब से दो रिपोर्ट तैयार करवाई गई, जबकि ये दोनों लैब सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं हैं। अकाल तख्त सचिवालय के मीडिया एडवाइजर जसकरण सिंह ने कहा कि यह इतिहास रहा है कि जो भी अकाल तख्त साहिब की चुनौती देता है, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है।

उदयनिधि का तमिलनाडु सीएम पर पत्नी को लेकर तंज

विपक्ष के नेता ने कहा- चेंगलपट्टू कोर्ट में पति की तलाश कर रही पत्नी

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु की राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता उधयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि चेंगलपट्टू कोर्ट में एक पत्नी अपने पति को खोज रही है।

स्टालिन ने यह टिप्पणी तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के संबोधन की शैली पर निशाना साधते हुए की। उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु को चेंगलपट्टू कोर्ट में पति को खोज रही पत्नी की कहानी पता है और मुख्यमंत्री को अब अभिनेता की छवि छोड़कर मुख्यमंत्री की भूमिका में व्यवहार करना चाहिए।

हालांकि स्टालिन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को मुख्यमंत्री विजय और उनकी अलग रह रही पत्नी संगीता सोर्नालिंगम से जोड़कर देखा जा रहा है। संगीता ने पिछले वर्ष दिसंबर में तलाक की याचिका दायर की थी, जिस पर चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

विजय ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकांश लोग पहले राजनीतिक दल बनाते हैं और बाद में जनता के बीच जाते हैं, जबकि उन्होंने पहले जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल किया और उसके बाद पार्टी बनाई। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को केवल अभिनेता की पार्टी कहकर खारिज करना गलत है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने 2026 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले लड़ा था।

पार्टी को केवल अभिनेता की पार्टी कहकर खारिज करना गलत... विजय इससे पहले सीएम विजय ने विधानसभा में अपने फिल्मी करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि वह सीधे फिल्म सेट से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यह सिर्फ एक 'रील' है।

मॉस्को में बोले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत

अदालतों के सामने जनता का भरोसा बनाए रखने की चुनौती

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि आज के समय में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालत पर आम जनता का भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने साफ किया कि इस चुनौती का एकमात्र समाधान जजों का ज्ञान, उनकी ईमानदारी और निष्पक्ष व तेजी से न्याय देने की उनकी प्रतिबद्धता है।

मॉस्को में भारतीय सुप्रीम कोर्ट और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बातचीत की शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये बातें कहीं। इस मौके पर रूस के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रास्नोव भी मौजूद थे।

तकनीक सिर्फ मदद के लिए- CJI: सीजेआई सूर्यकांत ने बदलते दौर में तकनीक और एआई की भूमिका पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक अदालतों का दायरा और उनकी पहुंच को बढ़ा सकती है, लेकिन न्याय की गुणवत्ता अंत में जजों की समझदारी, ईमानदारी और उनके समर्पण से ही तय होती है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तकनीक न्याय देने में मदद तो कर सकती है, लेकिन यह कभी भी न्यायिक मूल्यों और जजों के फैसलों की जगह नहीं ले सकती।

भारत में तकनीक से बदल रही है अदालतों की तस्वीर... मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि भारत में अदालतों को आम लोगों के लिए आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अब सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जैसे कि मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट। अदालती दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन उपलब्धता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई।

33 डिग्री टेंपरेचर और हुडी: लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज से बेनकाब हुआ मंगेतर सिया का प्रेमी

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे के पास लोहागढ़ किले में बिल्डर केतन अग्रवाल की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि केतन अग्रवाल और उसकी मंगेतर सिया गोयल का पीछा करते हुए हुडी पहने हुए एक व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस को यह बात अजीब लगी कि तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उस व्यक्ति ने हुडी पहनी हुई थी। उसकी संदिग्ध हरकतों को देखकर पुलिस ने केतन की मौत की और गहराई से जांच करने का फैसला किया, क्योंकि शुरुआत में यह मामला ट्रेकिंग के दौरान हुआ एक दुखद हादसा लग रहा था।

सिया ने घरवालों से बोला झूठ: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 18 जून को ट्रेकिंग के दौरान जान गंवाने वाले 26 साल के केतन को कथित तौर पर उसकी मंगेतर सिया (20) और उसके प्रेमी चेतन (22) ने खाई में धकेल दिया था। शुरू में इस घटना को दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया गया था क्योंकि सिया ने पीड़ित के परिवार को बताया था कि ट्रेकिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया था।

पुलिस को कब हुआ शक: जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'जांच के दौरान हमें घटना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिनसे शक हुआ और मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत महसूस हुई। हमने किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें केतन और सिया को एक साथ घूमते हुए देखा गया। फुटेज को बारीकी से देखने पर पुलिस ने एक आदमी को देखा जो केतन और सिया से कुछ मीटर पीछे था। अधिकारी ने कहा, 'उस आदमी ने शॉर्ट्स और हुडी पहनी हुई थी। हुडी का अगला हिस्सा इतना नीचे खींचा हुआ था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही उस आदमी ने हुडी के ऊपर हेडसेट भी पहना हुआ था। एक और फुटेज क्लिप में हमने देखा कि सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहने हुए वह आदमी अचानक नीचे बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने 18 जून को उस समय का तापमान चेक किया और पाया कि यह 33 डिग्री सेल्सियस था और उन्हें हैरानी हुई कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा।

सिया ने शादी टालने की कही थी बात: अधिकारी ने बताया कि केतन के परिवार के शोक में होने के कारण पुलिस तुरंत उस जोड़े से पूछताछ नहीं कर सकी, लेकिन जांच के दौरान केतन के चाचा से पता चला कि सिया ने पहले शादी को लेकर कुछ हिचकिचाहट जताई थी और एक बार पूछा था कि क्या शादी को एक साल के लिए टाला जा सकता है।

प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे केतन और सिया

उन्होंने कहा कि प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने से पहले सिया और चेतन मिलकर केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे। यह ट्रिप नहीं हो पाई क्योंकि ट्रिप से पहले ही केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सिया ने एक बार फिर केतन से 14 जून को लोहागढ़ जाने के लिए कहा। उस दिन उसने कथित तौर पर केतन को चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की। हालांकि, वह एक झाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा।

सिया की कॉल डिटेल से खुले राज

उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाक्रमों के बाद जांचकर्ताओं ने जांच का दायरा बढ़ाया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन डेटा सहित तकनीकी सबूतों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, सिया के कॉल रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि वह एक व्यक्ति के साथ लगातार बातचीत कर रही थी जो बाद में उसका प्रेमी चेतन चौधरी निकला। अधिकारी ने आगे बताया, 'टेक्निकल एनालिसिस से दोनों के बीच गहरा संबंध पता चला और एक सोची-समझी साजिश की ओर इशारा मिला। इसके बाद हमने चौधरी से जुड़ी तस्वीरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की। उन तस्वीरों की तुलना किले के सीसीटीवी फुटेज से करने पर हुडी पहने व्यक्ति को लेकर पुलिस को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली।'

ऐसे पकड़ा गया चेतन: उन्होंने आगे कहा कि इकट्ठा किए गए तकनीकी सबूतों और खुफिया जानकारी के आधार पर टीमों ने चौधरी का पता लगाया और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया।

गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में ड्रेस कोड लागू, अब हर स्वास्थ्यकर्मी की पहचान होगी आसान

गुरुग्राम, एजेंसी। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ड्रेस कोड को लेकर सख्ती दिखाई है। अब अस्पताल में तैनात कोई भी कर्मचारी बिना निर्धारित वर्दी और पहचान पत्र के ड्यूटी करता मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को यह पहचानने में परेशानी होती थी कि कौन नर्सिंग स्टाफ है और कौन पैरामेडिकल कर्मी या सुरक्षा कर्मचारी। इस स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सभी कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल टीम, वार्ड ब्वाय, सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी निर्धारित वर्दी के साथ अपना आइडी कार्ड भी प्रदर्शित करेंगे।

क्या होगा फायदा: मरीज आसानी से स्वास्थ्यकर्मियों की पहचान कर सकेंगे अस्पताल में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी मरीजों को जानकारी और सहायता लेने में होगी सुविधा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत कुछ स्वास्थ्यकर्मी ड्रेस कोट का पालन न करने की शिकायत मिल रही थी। निर्धारित ड्रेस कोड के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

गुजरात में सड़कों पर दौड़ता हुआ स्कूल, कबाड़ बसों को कैसे बनाया गया डिजिटल क्लासरूम

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात में सरकार ने 28 पुरानी बसों को सोलर पावर, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट टीवी, एलईडी लाइट के साथ खेलकूद के सामान से सुसज्जित कर नमक श्रमिकों के बच्चों के लिए मोबाइल क्लास रूम में तब्दील कर दिया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में इन बसों का लोकार्पण किया। बसों में बच्चों के बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, पुस्तकालय, ब्लैक बोर्ड और पेयजल के साथ बच्चों के खेलने की भी सुविधा है। बिना बिजली के भी ये बसें करीब 48 घंटे तक संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा सोलर पावर के चलते स्मार्ट टीवी, एलईडी लाइट आदि बिना किसी रुकावट के कार्य करते रहेंगे। एक बस में बीस छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा सकता है। इनमें से 20 बसें सुरेंद्रनगर जिले की पाटडी तहसील में, चार बसें पाटण के सांतलपुर तथा दो बसें कच्छ के अंजार में नमक श्रमिकों के बच्चों के लिए भेजी गई हैं।

मप्र में ईडी की 356 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई, 35.52 करोड़ की संपत्ति अटैच

इंदौर,एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए 35.52 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। ईडी द्वारा जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें इंदौर और शाजापुर जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट एवं भूमि के विभिन्न टुकड़े शामिल हैं। ये संपत्तियां आरोपित व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हैं। ईडी के इंदौर सब-जोनल कार्यालय द्वारा मंगलवार को जानकारी दी कि यह मामला एम/एस धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएसपीएल), उसके निदेशकों और उससे जुड़े संस्थानों और व्यक्तियों से संबंधित है। कंपनी पर बैंकों के साथ करीब 356.31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि बैंक फ्रॉड से अर्जित या उससे जुड़े धन के निवेश के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इसी के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैचमेंट) किया गया है। ईडी इस पूरे मामले में धन के स्रोत, उसके उपयोग और विभिन्न संपत्तियों में निवेश की पड़ताल कर रही है। जांच में कंपनी के निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे भी वित्तीय लेन-देन और अन्य संपत्तियों की जांच जारी रहेगी तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पर अभिषेक की त्वरित सुनवाई की मांग खारिज

कोलकाता,एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की आंख के इलाज के लिए विदेश जाने संबंधी मामले में त्वरित सुनवाई की मांग को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई सूची में आएगा और तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए मंगलवार को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके अधिवक्ताओं ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। बताया गया कि अभिषेक आंख के उपचार के लिए सात दिनों के लिए विदेश जाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर सामान्य रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उनके नाम से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और इन मामलों में उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसी कारण उन्होंने उपचार के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी है। उल्लेखनीय है कि, अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद में एक दलगत कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय अभिषेक बनर्जी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे।

सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, अंधेरी सबवे बंद मुंबई में आफत लाई मानसून की बारिश

मुंबई, एजेंसी। मानसून की पहली बारिश मंगलवार को मुंबई में आफत बनकर आई। सड़कें, रेलवे ट्रैक और सबवे सभी जगहों पर पानी भर गया और शहर के कई हिस्सों में जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार के लिए मुंबई में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। पूरे राज्य में बारिश का मौसम बने रहने के कारण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।

मंगलवार तक हुई भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया और सिविक अधिकारियों द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवाजाही पर रोक लगाने के कारण यात्रियों को ट्रैफिक में रुकावटों का सामना करना पड़ा। एवरार्ड नगर में पानी से भरे सबवे को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। साकी नाका मेट्रो स्टेशन इलाके समेत शहर के अलग-अलग हिस्सों की तस्वीरों में भारी बारिश का रोजमर्रा की आवाजाही पर असर साफ दिखा।

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई लोकल की ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रैक खराब होने की घटना के कारण अब तक 24 ट्रेनें रद कर दी गई हैं। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, मरम्मत के बाद प्रभावित हिस्से में ट्रैफिक तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन टर्भे और वाशी के बीच ट्रांस हार्बर लाइन के प्रभावित हिस्से में सावधानी बरतते हुए ट्रेनों की गति सीमित रखी गई है।

नहीं ढूंढ़ पाए समस्या का अस्थाई समाधान: अंधेरी अंडरपास की स्थिति के बारे में बात करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारी ऋतिक ने कहा, 'हम पानी भरने की इस गंभीर समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारे अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए यहां तैनात रहते हैं कि गाड़ियां यहां से न गुजरें। लेकिन कुछ रिक्शा चालक फिर भी अपनी गाड़ियों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। एक रिक्शा सबवे के बीच में फंस गया था। उसकी जान खतरे में थी। हमारे दो अधिकारियों ने उसे बाहर निकालने में मदद की।' बीएमसी के एक और अधिकारी रॉबर्ट ने कहा, 'हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अंडरपास के अंदर कोई भी गाड़ी न जाए।

रेल सेवा जारी रही

बीएमसी ने कहा कि पानी से भरे अंधेरी अंडरपास को छोड़कर सभी सबवे चालू रहे, जबकि शहर भर में रेल सेवा सामान्य रूप से चलती रही। जोरदार बारिश के बावजूद, वेस्टर्न रेलवे ने पुष्टि की कि सुबह के व्यस्त समय में हार्बर लाइन और चर्चगेट-दहानू कॉरिडोर समेत मुख्य रूटों पर सबअर्बन ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं। हालांकि, रात भर लगातार हुई बारिश के कारण मुंबई और नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया।

मुंबई में कितनी बारिश हुई

बीएमसी के बारिश के आंकड़ों के अनुसार, 23 जून को सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच शहर में औसतन 56 एमएम बारिश हुई, जबकि पूर्वी उपनगरों में 23 एमएम और पश्चिमी उपनगरों में 33 एमएम बारिश दर्ज की गई।

गाजियाबाद में 28 जून से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, 7.50 लाख बच्चों को मिलेगी खुराक

गाजियाबाद, एजेंसी। जिले में 28 जून से शुरू होने वाले विशेष पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। अभियान के लिए नौ लाख पोलियो वैक्सीन डोज मंगलवार को जिला स्टोर पहुंच गई। डोज को लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर और भोजपुर केंद्रों पर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने शून्य से पांच वर्ष तक के करीब 7.50 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिलेभर में 1600 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। दो हजार टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों तक पहुंचेंगी जो किसी कारणवश बूथों तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभियान की निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों में 22 सर्विलांस अधिकारियों की तैनाती की गई है। अभियान की तैयारी उस समय और तेज कर दी गई जब डूंडाहेड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने की जांच में पोलियो वायरस पुष्टि हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 12 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष सर्वे कराया। 107 टीमों ने 10 दिनों तक 31,100 घरों का सर्वे किया और 13,932 बच्चों के टीकाकरण की स्थिति का सत्यापन किया। सर्वे में 289 बच्चे ऐसे मिले जिन्हें पोलियो की खुराक नहीं मिली थी, जबकि 378 बच्चे पिछले दो चरणों में एक खुराक लेने से वंचित रह गए थे। हालांकि 12,786 बच्चों का दोनों चरणों में पूर्ण टीकाकरण होने की पुष्टि हुई।

भारत-मंगोलिया सहयोग: जयशंकर ने कीं कई उच्च-स्तरीय बैठकें कहा- 1.7 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना बेहद अहम

उलानबाटर, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को मंगोलिया में भारत की मदद से बन रही 1.7 अरब डॉलर की रिफाइनरी परियोजना निर्माण साइट का दौरा किया और काम की प्रगति का जायजा लिया। इस पहल के प्रगति दौरे पर उनके साथ मंगोलियाई समकक्ष बैटसेटसेग बैटमुंख और उद्योग-खनन मंत्री गोंगोर डमडिनन्याम भी मौजूद रहे। जयशंकर ने कहा, भारत-मंगोलिया दोस्ती की यह अहम परियोजना आगे बढ़ रही है। जयशंकर बोले, इस परियोजना में शामिल विभिन्न टीमों के साथ चल रहे काम की स्थिति सराहनीय है। उन्होंने परियोजना स्थल पर भारतीय और मंगोलियाई कर्मियों से चर्चा की और मुश्किल हालात में इतनी बड़ी परियोजना को साकार करने में उनके समर्पण व प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगोल तेल रिफाइनरी परियोजना भारत से 1.7 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से पूरी की जा रही है और यह मंगोलिया की टिकाऊ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। जयशंकर अपने दौरे के अंतिम चरण के लिए बुधवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे।

क्यूबा पर अमेरिका का नया आर्थिक प्रहार ट्रंप प्रशासन ने इन कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, संकट और गहराने की आशंका

वॉशिंगटन, एजेंसी। क्यूबा पहले से ही आर्थिक बदहाली, बिजली संकट और खाद्य कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अब अमेरिका ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा प्रहार किया है।

ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की पांच प्रमुख सरकारी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इन प्रतिबंधों से विदेशी निवेशकों में डर बढ़ेगा और क्यूबा का आर्थिक संकट और गहरा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें क्यूबा की सैन्य इकाई द्वारा संचालित कारोबारी समूह जीएईएसए से जुड़ी तीन कंपनियां भी शामिल हैं। जीएईएसए को क्यूबा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और माना जाता है कि देश की करीब 40 प्रतिशत जीडीपी पर इसका नियंत्रण है। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा की सरकार इन संसाधनों का इस्तेमाल जनता के कल्याण के बजाय अपने नियंत्रण को मजबूत करने और दमन के लिए कर रही है।

किन कंपनियों पर लगाया गया है प्रतिबंध: अमेरिका ने जिन पांच संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें अल्मासेनेस यूनिवर्सालेस एसए, राफिन एसए, बैंको फाइनेंसिएरो इंटरनेशनल एसए, जियोमिनेरा एसए और एम्प्रेसा सिडेरुर्गिका जोस मार्टी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की बहू अन्नाली लिलियम रुएडा कार्डेरो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की चिंता, नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी

प्योंगयांग, एजेंसी। उत्तर कोरिया ने 5,000 टन क्षमता वाले एक नए विध्वंसक युद्धपोत को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया है। देश के नेता किम जोंग उन ने इसे उत्तर कोरिया की बढ़ती नौसैनिक और परमाणु क्षमताओं का प्रतीक बताया है। सरकारी मीडिया की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्योंगयांग समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

युद्धपोत को नौसेना में किया गया शामिल: उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक, किम जोंग उन ने मंगलवार को पश्चिमी बंदरगाह शहर नाम्पो में आयोजित कमीशनिंग समारोह में कहा कि 'चोए ह्योन' नामक युद्धपोत इस बात का प्रमाण है कि नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है।

किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

- नौसेना को मजबूत करने पर किया फोकस।
- नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी।
- दक्षिण कोरिया से जल सीमा विवाद को लेकर बढ़ सकता है तनाव।

रूस ने की युद्धपोत बनाने में मदद

अप्रैल 2025 में इस युद्धपोत का अनावरण करने के बाद से इसके ट्रायल चल रहे थे। केसीएनए के अनुसार, यह युद्धपोत वायु रक्षा और पोत-रोधी हथियारों के अलावा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित कई उन्नत प्रणालियों से लैस है। हालांकि दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोत रूस की सहायता से तैयार किया गया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का संकेत है। तैनाती से पहले उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में चोए ह्योन का कई चरणों में परीक्षण किया, जिनमें पोत से परमाणु क्षमता वाली बताई गई क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण भी शामिल था।

बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बाद अब नौसेना को मजबूत करने पर फोकस

बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को वर्षों तक प्राथमिकता देने के बाद किम अब नौसैनिक क्षमताओं के विस्तार पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी के निर्माण की परियोजना भी शामिल है। फरवरी में वर्कर्स पार्टी की कांग्रेस में प्रस्तुत उनकी पांच वर्षीय सैन्य योजना में भी नौसैनिक शक्ति को प्रमुख महत्व दिया गया था। इस योजना में पानी के भीतर से प्रक्षेपित किए जा सकने वाले अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का लक्ष्य भी शामिल है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया जल्द ही एक नई समुद्री सीमा घोषित कर सकता है, जो दक्षिण कोरिया के नियंत्रण वाले जलक्षेत्र से टकराव पैदा कर सकती है।

दक्षिण कोरिया से तनाव बढ़ने की आशंका

दोनों कोरियाई देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच किम जोंग उन कई बार कह चुके हैं कि वे पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मौजूद नॉर्दर्न लिमिट लाइन को मान्यता नहीं देते। यह समुद्री सीमा 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान द्वारा निर्धारित की गई थी। दोनों देशों के बीच अतीत में इस विवादित सीमा पर कई घातक झड़पें हो चुकी हैं। मंगलवार के भाषण में किम ने कहा कि एक अन्य युद्धपोत कांग कोन भी जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया 10,000 टन क्षमता वाले एक और बड़े विध्वंसक युद्धपोत के निर्माण की योजना पर भी काम कर रहा है।

सिंगरौली में सीवरेज परियोजना तेज, एक माह में शुरू होंगे तीनों 31 एमएलडी एसटीपी

नगर निगम आयुक्त ने अमृत-1 योजना के तहत कार्यों की समीक्षा, शेष कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। अमृत-1 योजना के अंतर्गत सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में चल रही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) एवं सीवरेज नेटवर्क परियोजना के कार्यों में तेजी लाई गई है नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने गुरुवार को परियोजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए आयुक्त सविता प्रधान ने जिला पंचायत परिसर के समीप निर्माणाधीन एसटीपी तथा विंध्यनगर स्थित एसटीपी का स्थल निरीक्षण किया इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अमृत-1 योजना के अंतर्गत शहर में कुल तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 31 एमएलडी है।

तीनों एसटीपी अंतिम चरण में: जानकारी के अनुसार जोन-1 हिरवाह स्थित एसटीपी में केवल इलेक्ट्रिकल कार्य शेष है वहीं जोन-2 जिला पंचायत परिसर के समीप स्थित एसटीपी का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है इसी प्रकार जोन-3 विंध्यनगर स्थित एसटीपी में भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है जहां मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल कार्य शेष रह गया है आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी तकनीकी और निर्माण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक माह के भीतर तीनों एसटीपी को संचालन में लाया जा सके।

सीवरेज नेटवर्क कार्य में भी प्रगति: परियोजना के तहत कुल 79 किलोमीटर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है आयुक्त ने शेष पाइपलाइन बिछाने और सीवर कनेक्शन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर नागरिकों को शीघ्र लाभ उपलब्ध कराया जाए।

एप्रोच रोड निर्माण की भी समीक्षा: निरीक्षण के दौरान जोन-3 स्थित एसटीपी तक पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। संबंधित निर्माण एजेंसी को सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि संयंत्र तक सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके।

स्वच्छता व्यवस्था में आएगा सुधार: आयुक्त सविता प्रधान ने कहा कि तीनों एसटीपी का संचालन प्रारंभ होने के बाद शहर की सीवरेज व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा इससे न केवल स्वच्छता स्तर बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी परियोजना के पूर्ण होने के बाद शहर को एक आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज प्रणाली का लाभ प्राप्त होगा।

सीधी में वनरक्षक भर्ती में अजीब स्थिति, 8 पदों के लिए केवल एक अभ्यर्थी उपस्थित, 7 पद रिक्त

बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय के लिए विशेष भर्ती में 25 में से सिर्फ एक उम्मीदवार पहुंची, चयन प्रक्रिया पूरी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक असामान्य स्थिति सामने आई है, जहां पिछड़ी आदिम जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया समुदाय के लिए आरक्षित 8 पदों की विशेष भर्ती में केवल एक ही अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुई इस कारण 7 पद रिक्त रह गए। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2026 की विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत वन मंडल सीधी में कुल 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें 5 पद सामान्य (ओपन), 1 पद भूतपूर्व सैनिक तथा 2 पद होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए आरक्षित थे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद कुल 25 पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक मापजोख एवं पैदल चाल परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार चयन प्रक्रिया के लिए समिति गठित की गई थी वन मंडल रीवा एवं सीधी के अधिकारियों की उपस्थिति में 23 जून को चयन प्रक्रिया आयोजित की गई।

एकमात्र अभ्यर्थी ने पूरी की प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित तिथि पर केवल एक महिला अभ्यर्थी उपस्थित हुई जो उमरिया जिले की निवासी है अगले दिन पुरुष अभ्यर्थियों की पैदल चाल परीक्षा निर्धारित थी लेकिन उसमें कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। नियमों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर तथा पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर पैदल चाल पूरी करनी होती है। उपस्थित एकमात्र महिला अभ्यर्थी ने सभी निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसके बाद उसका चयन कर लिया गया।

वन विभाग ने दी जानकारी: वन मंडलाधिकारी प्रीति अहिरवार ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराई गई उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से 25 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन उपस्थिति बेहद कम रहने के कारण अधिकांश पद रिक्त रह गए।

पद रिक्त रहने से उठे सवाल: इस विशेष भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने से 7 पद रिक्त रह गए हैं जिससे भर्ती प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित इस विशेष अभियान में अपेक्षित भागीदारी न होने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी इसे गंभीर विषय माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 42 नवयुगल बने जीवनसाथी, गूंजे मंगलगीत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत पनवार स्थित सिद्धि विनायक पैलेस में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में जनपद पंचायत सीधी क्षेत्र के 42 नवयुगल वैवाहिक बंधन में बंधे। पारंपरिक रीति-रिवाजों, वैदिक मंत्रोच्चार और गाजे-बाजे के बीच सम्पन्न इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और जनकल्याण की भावना को साकार किया पूरे कार्यक्रम के दौरान मंगलगीतों की गूंज और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। समारोह में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सीधी रीती पाठक तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह परिहार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया इस अवसर पर प्रत्येक जोड़े को 49 हजार रुपये की सहायता राशि तथा गृहस्थी प्रारंभ करने हेतु आवश्यक उपहार भी प्रदान किए गए।

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का माध्यम: सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है इस योजना ने बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और सहज बनाकर अभिभावकों की बड़ी चिंता को दूर किया है उन्होंने कहा कि सरकार गरीब एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है जो जन्म से लेकर आत्मनिर्भर जीवन तक सहयोग प्रदान करती हैं उन्होंने उपस्थित लोगों से नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प भी दिलाया तथा नवविवाहित दंपतियों के सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना की विधायक रीती पाठक ने सभी नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है ।

सिंगरौली में राजस्व वसूली पर सख्ती, 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका, दो निलंबित

नगर निगम आयुक्त की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर कार्रवाई, अवैध नल कनेक्शन व लंबित शिकायतों पर भी सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नगर पालिक निगम सिंगरौली कार्यालय में मंगलवार को आयुक्त सविता प्रधान की अध्यक्षता में राजस्व वसूली एवं विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रहण की स्थिति, नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान कई वार्डों में राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

10 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोका: वार्डवार समीक्षा में पाया गया कि कई क्षेत्रों में राजस्व वसूली अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है इस पर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 वार्ड प्रभारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर वार्ड प्रभारी नवल किशोर एवं अशोक कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं दो अन्य कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अच्छा कार्य करने वालों की सराहना: बैठक में जहां लापरवाही पर कार्रवाई की गई वहीं बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सराहना भी की गई आयुक्त सविता प्रधान ने मो. वकील और वैभव गोस्वामी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अन्य कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी।

अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई के निर्देश: आयुक्त ने अधिकारियों को शहर में अवैध नल कनेक्शनों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने तथा समग्र आईडी, संबल योजना एवं सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश: आयुक्त सविता प्रधान ने स्पष्ट कहा कि राजस्व संग्रहण नगर निगम की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

एनएफएसए के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण, री-ईकेवाईसी अभियान जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी पांच वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुकी है उनके लिए शासन के निर्देशानुसार री-ईकेवाईसी प्रक्रिया संचालित की जा रही है ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं रिकॉर्ड का समय-समय पर अद्यतन सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के निर्देशानुसार पीओएस मशीनों में ऐसे हितग्राहियों को पीले रंग से प्रदर्शित किया जा रहा है जिनकी ई-केवाईसी पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है और जिन्हें पुनः री-ईकेवाईसी कराना आवश्यक है विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह एक नियमित एवं सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल डाटाबेस को अद्यतन रखना है। जिले में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुल 10 लाख 38 हजार 539 हितग्राही पंजीकृत हैं और सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी है शासन द्वारा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट प्रदान की गई है विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में 39 हजार 846 ऐसे सदस्य चिन्हित किए गए हैं, जिनकी ई-केवाईसी को पांच वर्ष से अधिक समय हो चुका है।

रैम्प कार्यशाला में उद्यमिता, नवाचार और डिजिटल बिजनेस पर जोर, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की रैम्प (रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना के अंतर्गत जिला सीधी में आयोजित दो दिवसीय एमएसएमई कम्पोजिट कार्यशाला का द्वितीय दिवस तकनीकी सत्रों, विशेषज्ञ संवाद एवं उद्यमिता प्रोत्साहन गतिविधियों के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में जिले के उद्यमियों, संभावित उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), स्टार्टअप्स एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक व्यवसायिक अवसरों और शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सीधी रीती पाठक ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार योजनाएं युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम हैं उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्थानीय स्तर पर नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। विधायक ने भोपाल से आई रैम्प टीम, रैम्प हेल्पडेस्क तथा जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सीधी द्वारा किए गए सफल आयोजन की सराहना की उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान एवं तकनीकी जानकारी को अपने व्यवसाय में व्यवहारिक रूप से अपनाएं तथा सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ें साथ ही उन्होंने रैम्प टीम एवं जिला उद्योग केंद्र से निरंतर संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा दो पात्र हितग्राहियों को विधायक रीती पाठक के माध्यम से ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए इस पहल से लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी तथा जिले में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

मोहर्रम की शहादत की रात आज, चौकों पर रखे जाएंगे ताजिय

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला मोहर्रम कमेटी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मोहर्रम की 9वीं तारीख अर्थात शहादत की रात आज शहर एवं जिले के विभिन्न ताजिया चौकों पर ताजिये स्थापित किए जाएंगे रात 12 बजे के बाद ताजियों को चौकों पर रखकर फातेहा, दरूद और लंगर का आयोजन किया जाएगा इसके साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबी मोहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोजा भी रखेंगे।

मोहर्रम पर्व के अवसर पर मंगलवार रात शहर में पारंपरिक मेहंदी जुलूस निकाला गया। पचमठा घोघर स्थित वसीम उर्फ मून के निवास से मेहंदी जुलूस की शुरुआत हुई जुलूस पचमठा मार्ग, एस.के. स्कूल के पीछे से होते हुए विभिन्न मार्गों पर गश्त करता हुआ शाहभोलन सिटी कोतवाली पहुंचा इसके बाद फोर्ट रोड स्थित हजरत मुनौवर शाह बाबा के आस्ताने पर हाजिरी दी गई और अयाज अली चौक होते हुए घोघर तकिया स्थित हजरत मकबूल शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर पहुंचकर अकीदत पेश की गई जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया विभिन्न स्थानों पर फातेहा का आयोजन किया गया तथा पारंपरिक ढोल भी बजाए गए धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

जिले में 1.92 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में आगामी 28 जून से तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्ष तक की आयु के 1 लाख 92 हजार बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं कलेक्टर विकास मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान जिले का कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भारत ने पोलियो मुक्त देश का गौरव हासिल किया है और इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की दो बूंद पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने तथा अभिभावकों को बच्चों को पोलियो बूथ तक लाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि अभियान के प्रथम दिवस 28 जून को जिलेभर में 1189 पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य प्रमुख आवागमन स्थलों पर 29 ट्रांजिट टीमें तैनात रहेंगी ताकि यात्रा के दौरान भी कोई बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। अभियान के दूसरे एवं तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर ऐसे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी, जो पहले दिन किसी कारणवश बूथों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए विस्तृत माइकोप्लान तैयार किया गया है।

सीधी में युवा कांग्रेस ने उठाई 19 सूत्रीय मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के मझौली क्षेत्र में बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम 19 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा ज्ञापन में मुख्य रूप से आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या, फसलों को हो रहे नुकसान तथा सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया गया साथ ही गौशालाओं के संचालन को व्यवस्थित करने की मांग भी की गई। युवा कांग्रेस ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के कारण किसान लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

किसानों के लिए बिजली और संसाधनों की मांग: ज्ञापन में किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराने, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने तथा कृषि संसाधनों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही कार्यकर्ताओं ने जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने और अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने की भी मांग की उन्होंने कहा कि बिजली और कृषि से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं जिससे किसानों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

युवाओं और ग्रामीणों की समस्याएं भी शामिल: ज्ञापन में युवाओं से जुड़ी समस्याओं, रोजगार के अवसरों की कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा कांग्रेस धौहनी विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक सिंह चंदेल 'सनी', वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर शुक्ला, कांग्रेस नेता प्रदीप दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसडीएम ने दिया आश्वासन: मझौली एसडीएम आर.पी. त्रिपाठी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि इसे कलेक्टर के माध्यम से आगे भेजा जाएगा और सभी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रदीप दीक्षित ने कहा कि जनसमस्याओं को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों, युवाओं और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

पिछले बारह महीनों में भीषण अग्निकांड और उनसे न सीख पाने की त्रासदी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग एवं एनीमेशन सेंटर में 22 जून 2026 को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश युवा छात्र थे। किकई छात्र धुएं में फंस गए, कुछ ने खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की और कई दम घुटने से काल के गाल में समा गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन में आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी और अग्नि सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया गया था। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बार-बार होने वाले अग्निकांडों से देश कब सबक लेगा।

पिछले बारह महीनों पर नजर डालें तो देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े अग्निकांड हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों परिवार प्रभावित हुए। इनमें अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, औद्योगिक इकाइयां, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवासीय भवन शामिल रहे। लगभग हर घटना के बाद जांच बैठी, मुआवजे की घोषणा हुई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया और सुरक्षा संबंधी कमियां जस की तस बनी रहीं।

संपादकीय

जून 2026 में दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र के एक होटल में लगी भीषण आग ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली। इस घटना ने राजधानी में होटल सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी। जांच में सामने आया कि कई होटलों में अग्निशमन उपकरण या तो खराब थे या उनका रखरखाव नहीं किया गया था। होटल कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण भी पर्याप्त नहीं था। यही कारण रहा कि आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं निकल सके।

इसके पहले विभिन्न राज्यों में औद्योगिक इकाइयों में भी कई बड़े अग्निकांड सामने आए। रासायनिक कारखानों, प्लास्टिक उद्योगों और गोदामों में लगी आग ने भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अधिकांश मामलों में पाया गया कि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच नहीं की गई थी। कई इकाइयों में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नियमों के अनुरूप नहीं था। कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल गई। अस्पतालों में लगी आग की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी रहीं। पिछले वर्षों में कई अस्पतालों में आग लगने से मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अनेक अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट समय पर नहीं हो रहे हैं। कई भवनों में निकासी मार्ग बाधित रहते हैं और बिजली व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं होती। अस्पतालों जैसे संवेदनशील संस्थानों में ऐसी लापरवाही सीधे मानव जीवन को खतरे में डालती है। शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वर्ष 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे।

अपने दल से अलग क्यों जा रहे सांसद

सुरेश हिंदुस्तानी

राजनीति में अवसर की तलाश करना आज के राजनेताओं का प्रिय विषय बनता जा रहा है। सीधे शब्दों इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि राजनीति अब सेवा का मार्ग न होकर अवसरवादिता के आवरण को ओढ़ चुकी है। विपक्षी दलों खास कर तृणमूल कांग्रेस और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों का अलग होना कहीं न कहीं यही संकेत करता है कि ये सांसद अपने पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने अपना खुद का एक राजनीतिक पाला बना लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि अब विपक्ष की संभावनाएं धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष की राजनीति का एक ही मुद्दा रह गया है, वह है आरोप की राजनीति। तुम आरोप लगाते रहो, हम काम करते जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ इसी प्रकार का खेल चल रहा है। यह बात सच है कि केवल आरोप लगाने की राजनीति के माध्यम से सत्ता का सिंहासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित और जनहित की ओर जाना ही होगा। आज की राजनीतिक स्थिति का विचार किया जाए तो यह कहना उचित ही होगा कि भाजपा का प्रचार सत्ता पक्ष की ओर से कम विपक्ष की ओर से ज्यादा किया जा रहा है। आज विपक्ष के नेताओं के बयान बिना भाजपा के अधूरे ही रहते हैं।

राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि आज का राजनेता किसी न किसी हेतु के लिए ही राजनीति कर रहा है, ऐसे राजनेता की न तो किसी दल से वैचारिक समानता होती है और न ही किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति निष्ठा ही रहती है। ऐसे राजनेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के अवसर की तलाश करते हैं। वर्तमान में विपक्षी राजनीतिक दलों के जो सांसद अपने दलों को छोड़ रहे हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं, वे अब शायद यह समझने लगे हैं कि उनका भविष्य अपने दल के साथ सुरक्षित नहीं है। इसका कारण यही है कि भारत की जनता को भारत के विकास की राजनीति पसंद आने लगी है। दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भाजपा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दल पूरा जोर लगाने के बाद भी पराजित होते जा रहे हैं। भविष्य में इनको सफलता मिलेगी, इसकी फिलहाल कोई गुंजाईश भी नहीं है।

वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग राह पर जा चुके हैं। इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत भी बेअसर हो गई है। और इसी कारण उनकी पार्टी आज एक डूबता हुआ जहाज की परिकल्पना को चरितार्थ करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जाता कि जब किसी के ताकत होती है, तो उसके पास अनेक लोग खड़े हो जाते हैं, और उसके शक्तिहीन होने पर कभी खास बनने वाले लोग भी दूरी बना लेते हैं। विपक्ष की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक समय ताल ठोकने वाली ममता बनर्जी के पास अब पहले जैसा रुतबा नहीं होगा और न ही विपक्ष में उनकी बात को कोई तबज्जो मिलेगा। इतना ही नहीं एक समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होने वाली ममता के लिए अब कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीति करने की मज़बूरी बन गई है, जो ममता बनर्जी को न तो पहले स्वीकार था और न ही वे अब स्वीकार करेंगी।

जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के अपने दल से बागी होने की बात है तो यह कहना समीचीन ही होगा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष के भविष्य की संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा विराम सा लगा हुआ दिखाई देता है। विपक्ष के राजनीतिक दल किसके नेतृत्व में एक होंगे, यह बड़ा सवाल है। जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के वे नेता जो हाँ में हाँ मिलाते हुए राजनीति करते थे वे अब प्रासंगिक होने लगे हैं। इनका प्रासंगिक होना ही विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि शक्ति केंद्र एक स्थान पर होता है तो उसकी बात का महत्त्व होता है, लेकिन यही शक्ति जब विभाजित हो जाती है, तब वह शक्तिहीन की श्रेणी में ही आती है। आज विपक्ष के राजनीतिक दल किसी एक दल के नेतृत्व में आने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारतीय संस्कृति और दर्शन ने सदैव संतोष को सर्वोच्च गुण माना है

वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्ची खुशियाँ बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने साधनों के अनुरूप जीवन जीने और सीमित इच्छाओं में संतोष खोजने में निहित हैं। आवश्यकता केवल इस सत्य को पहचानने और अपनाने की है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ सीमित हैं, किंतु इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह क्रम जीवनभर चलता रहता है। यही कारण है कि अनेक बार अत्यधिक संपन्न व्यक्ति भी मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा रहता है, जबकि सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी संतोष और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करता दिखाई देता है। यह अंतर धन या संसाधनों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है। जिसने संतोष का महत्व समझ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली।

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर आज का युग अभूतपूर्व प्रगति, तकनीकी विकास और भौतिक सुविधाओं का युग है। मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा अधिक संसाधन, अधिक अवसर और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि संतोष, शांति और खुशी की कमी पहले से अधिक दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की इच्छाएँ उसके साधनों और आवश्यकताओं से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। वह जो प्राप्त कर चुका है, उससे संतुष्ट होने के बजाय जो नहीं मिला है, उसकी चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच्ची खुशियाँ बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने साधनों के अनुरूप जीवन जीने और सीमित इच्छाओं में संतोष खोजने में निहित हैं। आवश्यकता केवल इस सत्य को पहचानने और अपनाने की है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ सीमित हैं, किंतु इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह क्रम जीवनभर चलता रहता है। यही कारण है कि अनेक बार अत्यधिक संपन्न व्यक्ति भी मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा रहता है, जबकि सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी संतोष और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करता दिखाई देता है। यह अंतर धन या संसाधनों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का है। जिसने संतोष का महत्व समझ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली साथियों, भारतीय संस्कृति और दर्शन ने सदैव संतोष को सर्वोच्च गुण माना है। हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि व्यक्ति के मन में संतोष है तो वह सीमित संसाधनों में भी सुखी रह सकता है, किंतु यदि संतोष नहीं है तो अपार धन-संपत्ति भी उसे खुश नहीं रख सकती। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ राजाओं और सम्राटों के पास असीमित वैभव था, फिर भी वे मानसिक शांति की तलाश में भटकते रहे। दूसरी ओर अनेक संत-महात्मा अत्यंत साधारण जीवन जीते हुए भी आनंद और आत्मिक संतुष्टि से परिपूर्ण रहे।वर्तमान समय में उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा ने इच्छाओं को और अधिक बढ़ा दिया है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति ने लोगों के मन में यह धारणा पैदा कर दी है कि अधिक वस्तुएँ, अधिक धन और अधिक प्रतिष्ठा ही

खुशी का आधार हैं। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी के पास नई कार है तो दूसरे को उससे बड़ी कार चाहिए, किसी के पास बड़ा घर है तो दूसरे को उससे अधिक भव्य घर चाहिए। इस अंतहीन दौड़ में व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाता है। परिणामस्वरूप उसे न तो वर्तमान का आनंद मिलता है और न ही भविष्य की कोई निश्चित खुशी।

साथियो, इच्छाओं का अनियंत्रित विस्तार केवल मानसिक तनाव ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। अनेक लोग अपनी आय से अधिक खर्च करने लगते हैं, ऋण के बोझ तले दब जाते हैं और फिर चिंता तथा अवसाद का शिकार हो जाते हैं। परिवारों में कलह, रिश्तों में दूरी और सामाजिक असंतुलन का एक बड़ा कारण भी यही असीमित इच्छाएँ हैं। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक पाने की लालसा में जीने लगता है, तब उसके जीवन से संतुलन समाप्त होने लगता है।इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने साधनों के अनुसार जीवन जीता है, वह मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुलित रहता है। वह अपनी उपलब्धियों का आनंद लेता है और जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाता है। परिवार के साथ बिताया गया समय, मित्रों का स्नेह, प्रकृति का सौंदर्य, स्वस्थ शरीर और शांत मन उसके लिए अमूल्य संपत्ति बन जाते हैं। यही वास्तविक सुख है, जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता।

साथियो संतोष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी न बने या प्रगति का प्रयास छोड़ दे। संतोष और आलस्य में अंतर है। व्यक्ति को अपने विकास, शिक्षा, व्यवसाय और समाजसेवा के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए, किंतु उन प्रयासों के पीछे अंधी लालसा नहीं, बल्कि सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए। जब प्रयास और संतोष का संतुलन बन जाता है, तब जीवन में सफलता भी आती है और शांति भी बनी रहती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इच्छाएँ हमारी आवश्यकताओं और क्षमताओं पर हावी हो जाती हैं।

विश्व के अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी यह सिद्ध किया है कि अत्यधिक भौतिकवाद व्यक्ति की खुशी को बढ़ाने के बजाय कम कर देता है। शोध बताते हैं कि एक सीमा तक आर्थिक सुरक्षा और सुविधाएँ जीवन को बेहतर बनाती हैं, लेकिन उसके बाद खुशी का स्तर मुख्यतः मानसिक संतोष, रिश्तों की गुणवत्ता और जीवन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अर्थात् खुशी का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि मन संतुष्ट है तो साधारण परिस्थितियाँ भी सुखद लगती हैं, और यदि मन असंतुष्ट है तो सर्वोत्तम परिस्थितियाँ भी अपर्याप्त प्रतीत होती हैं।

साथियों, प्रकृति हमें संतुलन का संदेश देती है। पेड़ अपनी आवश्यकता भर जल और पोषण लेकर फल-फूल देते हैं। नदियाँ बिना किसी लालच के निरंतर बहती रहती हैं। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का सौंदर्य संतुलन और संयम में है। मनुष्य यदि इस संदेश को समझ ले तो उसका जीवन अधिक सरल, सुखी और सार्थक बन सकता है।परिवार और समाज में भी संतोष की भावना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, संतुलित जीवन और संतोषपूर्ण मानसिकता में निहित है। यदि नई पीढ़ी को केवल उपभोग और प्रतिस्पर्धा का संदेश दिया जाएगा तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि उसे कृतज्ञता, सादगी और संतोष के मूल्य सिखाए जाएँगे तो वह अधिक खुशहाल और जिम्मेदार नागरिक बनेगी।आज विश्व अनेक संकटों का सामना कर रहा है–पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता। इन समस्याओं की जड़ में भी कहीं न कहीं मनुष्य की असीमित इच्छाएँ और अनियंत्रित उपभोग की प्रवृत्ति है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझकर सीमित उपभोग की आदत अपनाए, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज और पृथ्वी का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस दृष्टि से संतोष केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि वैश्विक कल्याण का आधार भी है।जीवन में सच्ची खुशियों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर हम खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ देते हैं–जब अधिक धन मिलेगा, बड़ा घर बनेगा या कोई विशेष लक्ष्य पूरा होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह सोच हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देती है। वास्तविक खुशी वर्तमान क्षण में जीने, जो प्राप्त है उसकी सराहना करने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।

अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की इच्छाएँ जितनी सीमित होंगी और संतोष की भावना जितनी प्रबल होगी, जीवन उतना ही सुखमय बनेगा। अपने साधनों के अनुरूप जीवन जीना, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से दूर रहना, उपलब्ध संसाधनों के प्रति कृतज्ञ होना और आत्मिक संतोष को महत्व देना ही वास्तविक समृद्धि है। सच्ची खुशियाँ महँगी वस्तुओं, भव्य भवनों या अपार धन-संपत्ति में नहीं, बल्कि उस संतुष्ट मन में छिपी होती हैं जो यह कह सके कि ÷मेरे पास जो है, वह पर्याप्त है और मैं उसके लिए आभारी हूँ।÷इसलिए आइए, हम अपनी इच्छाओं को विवेकपूर्ण सीमा में रखें, अपने साधनों के अनुरूप जीवन जीना सीखें, तुलना और दिखावे की संस्कृति से दूरी बनाएँ तथा संतोष को अपने जीवन का आधार बनाएँ। तभी हम उस सच्ची खुशी को पहचान पाएँगे जो सदैव हमारे आसपास और हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे देखने और महसूस करने की आवश्यकता है।

आपातकाल का अंत कितना भयावह : लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा

आपातकाल न तो पढ़ा था न पहले कभी देखा था अचानक आए राजनीतिक तूफान ने देश में अफरातफरी मचा दी। देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। लगभग 21 महीनों तक चले इस दौर ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। मार्च 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब देश ने राहत की सांस तो ली, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा, भय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई क्षति लंबे समय तक महसूस की गई।आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी।

सौरभ वार्ष्णेय

25 जून 1975 की आधी रात का काला अध्याय कैसे कोई भूल सकता है? गर्मी, तपिश और आंधी ने तो जनमानस को पहले से ही झुलसा रखा था ऊपर से रेडियो पर आया संदेश से पूरा देश सकते में आ गया। आपातकाल न तो पढ़ा था न पहले कभी देखा था अचानक आए राजनीतिक तूफान ने देश में अफरातफरी मचा दी। देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। लगभग 21 महीनों तक चले इस दौर ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। मार्च 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब देश ने राहत की सांस तो ली, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा, भय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई क्षति लंबे समय तक महसूस की गई।आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अखबारों को सरकारी अनुमति के बिना समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। विरोधी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया। लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी।

आपातकाल के अंतिम चरण में सबसे अधिक आलोचना जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाइयों को लेकर हुई। कई स्थानों पर प्रशासनिक दबाव में लोगों को नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीब और कमजोर वर्ग इस नीति का सबसे बड़ा शिकार बना। इससे जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। अनेक परिवारों ने सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेले, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है।

हालांकि, मार्च 1977 के आम चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को भी साबित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और जनता ने मतदान के माध्यम से अपना फैसला सुनाया। पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण था।आपातकाल की समाप्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा लगाव रखती है। सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जनता ही सर्वोच्च होती है। इस दौर ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। आज,आपातकाल के पांच दशक बाद भी यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में याद की जाती है। इसका संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन से मजबूत होता है। आपातकाल का अंत भयावह अनुभवों और लोकतंत्र की पुनर्जागृति दोनों का प्रतीक था। यह इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक ही होते हैं।

आपातकाल के काले छींटे कब सुलझेंगे?

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसे आज भी काला अध्याय कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए थे। लगभग 21 महीने तक चले इस दौर में हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विरोध के हर स्वर को दबाने का प्रयास किया गया। आज, आपातकाल समाप्त हुए पाँच दशक के करीब समय बीत चुका है, लेकिन उसके काले छींटे पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं। इसका कारण केवल इतिहास की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को लेकर लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां भी हैं। जब भी सत्ता के केंद्रीकरण, संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विपक्ष की भूमिका पर बहस होती है, तब आपातकाल की याद स्वतः ताजा हो जाती है। आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यह था कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया और जागरूक नागरिकों से संचालित होता है। यदि इनमें से किसी भी स्तंभ को कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आपातकाल की घटनाओं का स्मरण केवल अतीत को कोसने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।दुर्भाग्य से, आपातकाल पर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। एक पक्ष इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताता है, जबकि दूसरा पक्ष वर्तमान परिस्थितियों की तुलना उस दौर से करने का प्रयास करता है। इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच वास्तविक आवश्यकता यह है कि देश उस कालखंड का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और उससे मिले सबकों को आत्मसात करे। आपातकाल के काले छींटे तभी पूरी तरह सुलझेंगे जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समाज और शासन दोनों की प्रतिबद्धता अटूट होगी। नागरिक अधिकारों का सम्मान, सत्ता की जवाबदेही, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती ही उस अंधकारमय दौर की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। इतिहास को भुलाना समाधान नहीं है; उससे सीख लेकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपातकाल को केवल राजनीतिक विमर्श का विषय न बनाया जाए, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का स्थायी पाठ बनाया जाए। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तथा शासन संविधान की मर्यादाओं के भीतर कार्य करेगा, तभी आपातकाल के वे काले छींटे वास्तव में मिट सकेंगे और भारत का लोकतंत्र और अधिक परिपक्व तथा सशक्त बन सकेगा।

महिला आयोग का सख्त रुख: खदान दुर्घटना पीड़िता को मुआवजा और रोजगार दिलाने की पहल

एमसीबी जिले में महिला आयोग की सुनवाई में 11 मामलों पर हुई कार्रवाई, 5 प्रकरणों का मौके पर निराकरण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। महिलाओं को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में बुधवार को महिला आयोग की विशेष सुनवाई आयोजित की गई प्रदेश स्तर पर यह 403वीं तथा जिला स्तर पर दूसरी सुनवाई रही सुनवाई के दौरान एमसीबी जिले से संबंधित कुल 11 प्रकरणों पर विचार किया गया जिनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया गया। सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण मामला खदान दुर्घटना में मृत कर्मी की पत्नी से जुड़ा रहा आवेदिका ने आयोग को बताया कि उसके पति स्वर्गीय नर्मदा सिंह बेस्ट कॉलरी चिरमिरी में कार्यरत थे और खदान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना के बाद न तो परिवार को मुआवजा मिला और न ही अनुकंपा नियुक्ति। आवेदिका को अस्थायी रूप से ठेका श्रमिक के रूप में काम दिया गया था लेकिन नवंबर 2025 में उसे भी हटा दिया गया। दो बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अकेले उठाने की स्थिति में उसने आयोग से सहायता की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिए कि आवेदिका को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने, वेतन संबंधी जानकारी एकत्र करने तथा मुआवजा भुगतान की स्थिति का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है तो आवश्यक अनुशंसा की जाएगी

भरण-पोषण मामले में आयोग सख्त: भरण-पोषण से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में आवेदिका अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ उपस्थित हुई, जबकि सभी अनावेदक अनुपस्थित रहे आवेदिका ने बताया कि वह अकेले बेटी का पालन-पोषण कर रही है और अनावेदक लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय होने के बावजूद कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रहा है उसने 15 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण राशि की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को बिलासपुर में निर्धारित की है साथ ही पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पत्र भेजकर सभी अनावेदकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाने का निर्णय लिया गया आयोग ने चेतावनी दी कि लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है।

घरेलू हिंसा और संपत्ति विवाद के मामलों पर भी सुनवाई: घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में दोनों पक्ष उपस्थित हुए, लेकिन समझौते के प्रयास के बावजूद आवेदिका ने साथ रहने से इंकार कर दिया आयोग ने विधिक कार्रवाई और सुलह प्रयास जारी रखने की सलाह देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवादों का निराकरण राजस्व अथवा दीवानी न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है आवश्यक कानूनी सलाह देने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया। महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए आयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि सुनवाई के माध्यम से महिलाओं को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी रहेगा।

ग्वालियर में फायर एनओसी के बिना चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, दो संस्थान सील

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग लगने की दुखद घटना के बाद ग्वालियर प्रशासन ने शहर के कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है नगर निगम के फायर ब्रिगेड दस्ते ने मंगलवार को विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फायर सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। जांच के दौरान नगर निगम की टीम सबसे पहले सी कृषि संस्थान कोचिंग पहुंची यहां लगाए गए कई अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, जबकि कुछ सिलेंडर पूरी तरह खाली पाए गए इसके अलावा संस्थान के पास फायर सेफ्टी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी इन कमियों को गंभीर मानते हुए निगम ने कोचिंग सेंटर को तत्काल सील कर दिया। इसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित विज्ञान पथ कोचिंग में भी निरीक्षण किया गया यहां भी कई अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट के मिले तथा कुछ खाली पाए गए। संस्थान के पास फायर सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। कार्रवाई करते हुए टीम ने कोचिंग संचालक के कार्यालय को सील कर दिया।

लाइब्रेरी में बंद मिले छात्र: निरीक्षण अभियान के दौरान एमएलबी कॉलोनी स्थित एक लाइब्रेरी में बड़ा मामला सामने आया नगर निगम और पुलिस को सूचना मिली कि वहां 60 से 70 छात्र-छात्राओं को अंदर बंद कर दिया गया है सूचना पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और ताला खुलवाकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर रजनीश गुप्ता के अनुसार कुछ छात्रों के छत के रास्ते बाहर निकलने का प्रयास करने की भी सूचना मिली थी प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फायर सुरक्षा जांच से बचने के लिए लाइब्रेरी संचालक ने बाहर से ताला लगाकर छात्रों को अंदर रोक दिया था।

शहर में सुरक्षा व्यवस्था चिंताजनक: जानकारी के अनुसार ग्वालियर में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 1050 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं इनमें लगभग 40 से 50 बड़े संस्थान हैं जहां प्रतिदिन हजारों छात्र अध्ययन के लिए पहुंचते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश संस्थानों के पास फायर एनओसी या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कई स्थानों पर आपातकालीन निकासी मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम और सुरक्षा संकेतक तक मौजूद नहीं हैं। नगर निगम के फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ नोटिस, सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल फायर एनओसी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है बल्कि संस्थानों को नियमित सुरक्षा ऑडिट, मॉक ड्रिल और आपदा प्रबंधन की तैयारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन अब इस विषय पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

सांख्य सागर झील में सीवर मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग और पीएचई को लगाई फटकार

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी स्थित सांख्य सागर झील में सीवर और गंदे पानी के प्रवाह को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के प्रति कड़ा रुख अपनाया है जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी अवैध गतिविधि के वर्षों से जारी रहने मात्र से वह वैध नहीं हो जाती कोर्ट ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं शिवपुरी निवासी आदित्य राज पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि माधव नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांख्य सागर झील में शहर का सीवर और नालों का गंदा पानी लगातार छोड़ा जा रहा है याचिका में कहा गया है कि इससे झील का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि संरक्षित क्षेत्र की झील में सीवर का पानी पहुंचना गंभीर पर्यावरणीय और कानूनी विषय है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है।

वन विभाग की दलील पर अदालत की नाराजगी: सुनवाई के दौरान माधव नेशनल पार्क के उप संचालक हरिओम व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले लगभग 25 वर्षों से झील में वेस्ट मटेरियल पहुंच रहा है और इसलिए इसमें किसी की दुर्भावना नहीं मानी जानी चाहिए। इस तर्क पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी अवैध कार्य लंबे समय से हो रहा हो तो भी वह कानून के दायरे में वैध नहीं माना जा सकता।

पुरानी रंजिश में किसान की झोपड़ी में लगाई आग, दो लाख का सामान जलकर खाक

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के नरवर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक किसान की खेत पर बनी झोपड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया है आगजनी की इस घटना में अनाज, बीज, कृषि उपकरण सहित घरेलू उपयोग का सामान जलकर खाक हो गया पीड़ित किसान ने करीब दो लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धुवाई तालाब के सामने रहने वाले 60 वर्षीय किसान पीरा शाह ने नरवर थाने में शिकायत दर्ज कराई है किसान ने बताया कि 23 जून की रात वह अपने खेत पर बनी पाटौर (झोपड़ी) में सो रहे थे देर रात कुछ संदिग्ध आवाज सुनाई देने पर उनकी नींद खुली जब वे पीछे की ओर गए तो उन्होंने अपने पड़ोसी हबीब शाह और नाजू शाह को झोपड़ी में आग लगाकर भागते हुए देखा। किसान ने तत्काल शोर मचाया, जिसके बाद उनका बेटा, बहू और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और पूरी झोपड़ी उसकी चपेट में आ गई थी ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। आगजनी की इस घटना में झोपड़ी में रखा गेहूं, आटा, फसल के बीज, कृषि उपकरण, बिजली का सामान और अन्य घरेलू सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई।

एमसीबी जिले में खुलेगा नया वृद्धाश्रम, निराश्रित बुजुर्गों को मिलेगा सुरक्षित आश्रय

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित आश्रय, बेहतर देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) में 25 हितग्राहियों की क्षमता वाले नवीन वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा इच्छुक एवं अनुभवी अशासकीय संस्थाओं, पंजीकृत लोक न्यासों तथा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं समाज कल्याण विभाग के अनुसार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एमसीबी जिले में नए वृद्धाश्रम की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है इस पहल का उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों को संरक्षण देना है जो निराश्रित हैं अथवा जिनके पास जीवनयापन और देखभाल के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

बुजुर्गों को मिलेंगी सभी आवश्यक सुविधाएं: प्रस्तावित वृद्धाश्रम में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा एवं देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इसके साथ ही मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। वृद्धाश्रम में प्रत्येक निवासी के लिए अलग बिस्तर, पलंग और आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा पुरुष एवं महिला हितग्राहियों के लिए पृथक सुविधाएं सुनिश्चित होंगी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, इनडोर खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। परिसर में स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और हरित वातावरण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुभवी संस्थाओं को मिलेगा संचालन का अवसर: समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि वृद्धाश्रम का संचालन केवल उन्हीं संस्थाओं को सौंपा जाएगा जो विभाग से मान्यता प्राप्त हों तथा सामाजिक क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखती हों प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा समिति की अनुशंसा के बाद अंतिम अनुमोदन के लिए प्रकरण समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर भेजा जाएगा।

ईओआई के साथ प्रस्तुत करने होंगे आवश्यक दस्तावेज: वृद्धाश्रम संचालन के इच्छुक संगठनों को आवेदन पत्र (ईओआई) के साथ संस्था का पंजीयन विवरण, विभागीय मान्यता प्रमाण पत्र, संस्था की नियमावली, कार्यक्षेत्र, कार्यालय का पता, भवन का विवरण, फोटोग्राफ, उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी तथा विगत तीन वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होंगे इसके अलावा टीआईएन/पैन नंबर, संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव, भवन स्वामी का सहमति पत्र या किरायानामा, कर्मचारी उपलब्धता का विवरण तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ जमा करनी होंगी।

मोहर्रम पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मोहर्रम पर्व के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 26 जून 2026 (शुक्रवार) के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति की है जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ लिंगराज सिदार को पुलिस अनुविभाग मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत थाना मनेन्द्रगढ़, थाना झगराखाण्ड, चौकी खोंगापानी तथा चौकी कोड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चिरमिरी/खड़गवां विजेन्द्र सारथी को पुलिस अनुविभाग चिरमिरी के थाना चिरमिरी, थाना खड़गवां, थाना पोंडी, चौकी कोरिया तथा चौकी नागपुर क्षेत्र के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे पर्व के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वहीं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भरतपुर शशि शेखर मिश्रा को पुलिस अनुविभाग भरतपुर के थाना जनकपुर, थाना कोटाडोल, थाना केल्हारी तथा चौकी कुंवारपुर क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है जिला प्रशासन ने सभी नियुक्त अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत जिले की 22 ग्राम पंचायतों में चार प्रकार के कचरे का होगा पृथक संग्रहण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू होने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले की 22 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण के तहत चार प्रकार के अपशिष्टों का पृथक संग्रहण किया जाएगा इस नई व्यवस्था के अंतर्गत गीला, सूखा, सेनेटरी एवं विशेष जोखिमपूर्ण अपशिष्ट को अलग-अलग एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रबंधन किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही इस पहल में जिले की 3 एनजीटी प्रभावित पंचायतों तथा 5 पर्यटन स्थलों वाली पंचायतों सहित चयनित ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार होगा तथा अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण एवं निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी घर-घर से पृथक कचरा संग्रहण कर निर्धारित श्रेणियों के अनुसार उसका प्रसंस्करण किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण बल मिलेगा विशेषज्ञों के अनुसार कचरे का पृथक्करण होने से हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी साथ ही जैविक कचरे से खाद एवं बायोगैस उत्पादन तथा सूखे कचरे के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) को बढ़ावा मिलेगा इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा और गांवों में कूड़े के ढेरों में कमी आएगी इसके अतिरिक्त सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को भी मजबूती मिलेगी, जिसके तहत अपशिष्ट को संसाधन के रूप में उपयोग कर खाद, बायोगैस, रिसाइक्लिंग तथा आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित किए जा सकेंगे।

खुले में कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई: ग्राम पंचायतों द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण व्यवस्था लागू किए जाने के बाद सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने अथवा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कचरा जलाने पर भी रहेगा प्रतिबंध: जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा लोगों को कचरे के पृथक्करण एवं उसके वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, बोले- परीक्षा केंद्र थे या युद्ध का मैदान

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक प्रकरण, किसानों की समस्याओं, मूंग खरीदी में अव्यवस्थाओं तथा खाद-यूरिया की कमी को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत पांडेय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार प्रभावित हो रही है। इस दौरान पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ और बाद में दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से परीक्षा कराने में विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा ने दोबारा आयोजित परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर जिस प्रकार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सैन्य अभियान चलाया जा रहा हो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि परीक्षा कराने के लिए सेना की सहायता लेना इस बात का संकेत है कि परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कई विद्यार्थियों को मात्र कुछ मिनट की देरी के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे अनेक छात्रों को निराशा का सामना करना पड़ा।

भ्रष्टाचार के आरोप लगाए: कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा संचालन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहली बार पेपर लीक होने के बाद किसी ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, जबकि दोबारा परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर उसका श्रेय लेने की कोशिश की गई।

किसानों की समस्याएं भी उठाई: प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। नेताओं ने कहा कि जिले के किसान इस समय मूंग खरीदी में आ रही समस्याओं, खाद और यूरिया की कमी तथा कृषि संबंधी अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं ।

मंदसौर में खेतों के बीच मिली एमडी ड्रग फैक्ट्री दो आरोपी गिरफ्तार, घर से 13 किलो 850 ग्राम जब्त

मीडिया ऑडीटर,मंदसौर (निप्र)। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मंगलवार को ग्राम बाजखेड़ी के निकट खेतों के बीच बने एक पक्के मकान पर दबिश देकर पुलिस ने 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स, 9 किलो 109 ग्राम केमिकल और ड्रग निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। वहीं मामले का खुलासा पुलिस ने बुधवार सुबह किया।

एसपी विनोद कुमार मीना के निर्देशन में गठित विशेष टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नई आबादी थाना क्षेत्र के ग्राम बाजखेड़ी में खेतों के बीच बने एक मकान में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक मादक पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश देकर तलाशी ली तो वहां अवैध रूप से संचालित एमडी ड्रग निर्माण इकाई का खुलासा हुआ।

ड्रग्स बनाने के उपकरण और केमिकल भी मिले: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स के अलावा 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ (केमिकल) जब्त किए। साथ ही ड्रग निर्माण में प्रयुक्त 2 स्टील के बड़े मटके, 3 स्टील के चम्मच, एक स्टील का तपेला, एक स्टील की तपेली, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन, एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, एक प्लास्टिक ड्रम, तीन प्लास्टिक बाल्टियां, ड्रग्स सुखाने में उपयोग की जाने वाली हैलोजन लाइटें तथा अन्य सामग्री भी बरामद की गई।पुलिस ने मौके से दो आरोपी सदाकत पिता लियाकत खान (41 वर्ष), निवासी अरोरा कॉलोनी, पटेल नगर, संजीत नाका, मंदसौर और आरिफ पिता नियाज अजमेरी (33 वर्ष), निवासी बाजखेड़ी को गिरफ्तार किया है वहीं ताहिर पिता फकरुद्दीन अजमेरी, निवासी बाजखेड़ी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है।

लंबे समय से फैक्ट्री संचालित होने की आशंका: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बाहर से कच्चा माल लाकर खेत पर बनी इस फैक्ट्री में एमडी जैसे सिंथेटिक मादक पदार्थ तैयार करते थे। तैयार माल को जिले सहित अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस को आशंका है कि यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी और इसके जरिए बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अब ड्रग्स के निर्माण, परिवहन और वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कच्चा माल कहां से लाया जाता था और तैयार ड्रग्स किन-किन क्षेत्रों में भेजी जाती थी। पुलिस का मानना है कि जांच में इस रैकेट से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।मामले में थाना नई आबादी पर अपराध क्रमांक 115/2026 दर्ज कर धारा 8/22/25/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया है। जब्त की गई समस्त सामग्री को विधिवत कब्जे में लेकर विवेचना शुरू कर दी गई है।

एसपी बोले - पूरे नेटवर्क को किया जाएगा ध्वस्त: बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने बाजखेड़ी गांव स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई की थी। मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स, करीब 19 किलो केमिकल तथा ड्रग्स निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं।

सोशल मीडिया चैट और अश्लील वीडियो से घिरा कांस्टेबल

खंडवा में महिलाओं को फंसाकर शोषण के आरोप,अब सीएसपी करेंगे जांच

मीडिया ऑडीटर,खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले के खालवा थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक अफराज मिर्जा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर वायरल चैट, फोटो और वीडियो के आधार पर उस पर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजी गई है, जबकि विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हिंदूवादी संगठन महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरक्षक अफराज मिर्जा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं और युवतियों से संपर्क करता था। वह अपनी पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें अपने करीब लाता था और बाद में शोषण करता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ महिलाओं के फोटो और वीडियो का दुरुपयोग कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

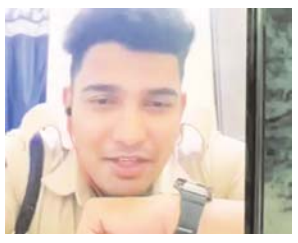

एएसपी बोले- चैट और फोटो प्रथम दृष्टया अशोभनीय: एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि पुलिस आरक्षक से जुड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया चैट, फोटो और वीडियो सामने आए हैं जो प्रथम दृष्टया अशोभनीय प्रतीत होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीएसपी खंडवा को सौंपी गई है।

मोबाइल और सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे: पुलिस ने बताया कि शिकायत और डिजिटल सामग्री की बारीकी से जांच की जाएगी। सोशल मीडिया अकाउंट, चैट, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।जानकारी के अनुसार अफराज मिर्जा की नियुक्ति पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर हुई थी। वह पहले जीआरपी थाने में पदस्थ रहा और बाद में जिला पुलिस में स्थानांतरित होकर कोतवाली थाने में तैनात किया गया था।

कोतवाली से हटाकर खालवा थाने भेजा गया था: सूत्रों के मुताबिक, उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इन्हीं कारणों से उसे कोतवाली से हटाकर खालवा थाने भेजा गया था। विभागीय स्तर पर उसके आचरण को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अफराज मिर्जा की शादी एक महिला कांस्टेबल से हुई थी, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद भी उसके आचरण को लेकर चर्चा बनी रही। मामले में यह भी दावा किया गया है कि आरक्षक के कथित तौर पर रेलवे और सेना से जुड़े कुछ अधिकारियों की पत्नियों से संपर्क रहे हैं। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।

रतलाम में मौसेरे भाई ने की किसान की हत्या

मीडिया ऑडीटर,रतलाम (निप्र)। रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र स्थित कोठड़ी गांव में 35 वर्षीय किसान राजेंद्रसिंह डांगी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। किसान की हत्या मासी के लड़के मौसेरे भाई ने की थी। हत्या के षड़यंत्र में आरोपी भाई की पत्नी, बेटा व छोटा भाई भी शामिल था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खेत के मेड़ (रास्ते) व समाज से बाहर करने की रंजिश के चलते हत्या की गई। शनिवार सुबह ताल के कोठड़ी गांव में किसान राजेंद्रसिंह का शव खून से लथपथ मिला था। किसान राजेंद्रसिंह शुक्रवार रात अपने खेत पर जुताई करने गए थे। सुबह तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन तलाश करने गए। खेत पर राजेंद्र सिंह का शव मिला था। शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या का केस मानकर जांच शुरू की। एसपी अमित कुमार ने आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर, ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी व आलोट थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, बरखेड़ाकला थाना प्रभारी पातिराम डावरे व सायबर सेल की जांच टीम बनाई। जांच में सामने आया कि किसान को उसी के मासी के लड़के उमरावसिंह (46)पिता नाथुजी डांगी निवासी ग्राम कोटड़ी खारवा ने खेत के रास्ते को लेकर पूर्व में विवाद कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस इसी एंगल से जांच करते हुए आगे बढ़ी। साइबर सेल, मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से संदेही को पकड़ा।

धारदार हथियार से हमला किया: संदेही मासी के लड़के उमरावसिंह डांगी को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि खेत की मेड़ के विवाद एवं सामाजिक रंजिश के चलते आरोपी उमरावसिंह डांगी ने अपने मासी के लड़के राजेंद्रसिंह डांगी को शुक्रवार रात खेत की जुताई करने के दौरान धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की साजिश में उमरावसिंह डांगी की पत्नी भूलीबाई (42), बेटा जितेंद्र (22) व उमरावसिंह का भाई जगदीश (42) भी शामिल थे। इन्होंने हत्या के दौरान पुलिस से जानकारी छिपाई। हत्या के षड़यंत्र में शामिल रहे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश किया। जहां से पुलिस रिमांड लेकर आगे की पूछताछ जारी है।

बागेश्वर धाम जा रही ओवरलोड ई-रिक्शा खाई में पलटी:एक महिला श्रद्धालु की मौत, दर्जनभर घायल

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)।छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बागेश्वर धाम जा रही एक ओवरलोड ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दुर्घटना में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, श्रद्धालु ट्रेन से ईशानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां से वे ई-रिक्शा टैक्सी के माध्यम से बागेश्वर धाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में भेलसी के समीप वाहन ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ई-रिक्शा सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 112 डायल पुलिस, स्थानीय ग्रामीण और राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। महिला श्रद्धालु की मौके पर मौत दुर्घटना में एक अधेड़ महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं, लगभग एक दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है।

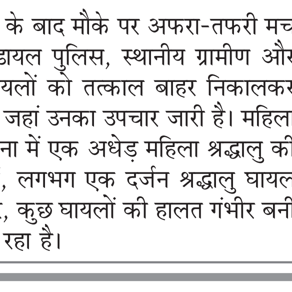

बीयू के रिटायर्ड कुलसचिव का मोबाइल-रुपए चुराने वाला अरेस्ट

बांद्राभान में कार खड़ी कर नर्मदा स्नान करने गए थे, आदतन अपराधी ने कांच फोड़ा

मीडिया ऑडीटर,नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम स्थित बांद्राभान में नर्मदा स्नान करने आए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी (BU) के रिटायर्ड कुलसचिव (रजिस्ट्रार) और कमांडेंट के परिवार की कार का कांच फोड़कर चोरी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कार से आईफोन 16 और 4 हजार रुपए नकद पार कर दिए थे। देहात थाना पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से इस आदतन अपराधी को दबोच लिया है।

जानकारी के अनुसार, भोपाल निवासी फरियादी प्रोफेसर डॉ. पंकज भारती 20 जून की शाम अपने पिता डॉ. बी भारती (बीयू के रिटायर्ड कुलसचिव), भाई डॉ. नीरज भारती (कमांडेंट), मां और बच्चों के साथ नर्मदा स्नान के लिए बांद्राभान आए थे। संगम स्थल पर स्नान करने के बाद जब वे वापस कार के पास लौटे, तो गाड़ी के गेट का कांच फूटा देखकर घबरा गए। उन्होंने देखा कि अंदर रखे पर्स से 4 हजार रुपए नकद और एक आईफोन गायब था। इसके बाद उन्होंने तत्काल डायल-112 पर कॉल कर सूचना दी। पुलिस ने रात 11 बजे देहात थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की।सीसीटीवी न होने से आई परेशानी, मुखबिर ने की मदद देहात थाना प्रभारी ऊषा मरावी ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने चोरी किया गया आईफोन बंद कर लिया था। घटनास्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या तकनीकी साक्ष्य मौजूद नहीं होने के कारण आरोपी की पहचान करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। ऐसे में पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही नीरज वर्मा (पिता राजकुमार वर्मा, उम्र 26 वर्ष) को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की, तो उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।

रतलाम-बांसवाड़ा रोड पर ट्रक-बाइक भिड़ंत, चचेरे भाई-बहन की मौत

हादसे के बाद भागा ड्राइवर , दानपुर के आगे ट्रक पकड़कर पुलिस ने किया जब्त

मीडिया ऑडीटर,रतलाम (निप्र)। रतलाम-बांसवाड़ा रोड पर रविवार रात ट्रक व बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार महिला-पुरुष दूर जा गिरे। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर रात में पुलिस पहुंची। घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपे।

हादसे में दुर्गा (40) पति रकमा खराड़ी व अरविंद उर्फ कालू (25) पिता ईश्वर निनामा दोनों निवासी तलवानी सरवन थाना की मौत हो गई। सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। मृतक रिश्ते में चचेरे भाई बहन हैं। पल्सर बाइक से आ रहे थे। रात में यह दोनों पल्सर बाइक से गांव तलवानी से सरवन की तरफ किसी रिश्तेदारी के कार्यक्रम में जा रहे थे। इस दौरान सरवन थाने से करीब 1 किमी दूर गांव श्यामपुरा के पास रतलाम की तरफ से आर रहे सोयाबीन से भरे ट्रक से भिंड़त हो गई। जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। रात में दोनों के शव मेडिकल कॉलेज भेजे गए। सुबह पीएम के बाद परिजनों को शव सौंपे।उज्जैन से बांसवाड़ा जा रहा था ट्रक

ट्रक उज्जैन से सोयाबीन भरकर राजस्थान के बांसवाड़ा जा रहा था। रात में टक्कर की सूचना के बाद पुलिस ने दानपुर तक रोड पर ट्रक की सर्चिंग की। सीसीटीवी भी देखे। सर्चिंग के दौरान एक ट्रक दानपुर के आगे खड़ा मिला। ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन उसने किसी भी दुर्घटना से मना किया।

खर्रादार नदी के पास चौकीदार का शव मिला पुल की साइट पर देखरेख का काम करते थे, बालाघाट में 4 दिन से लापता थे

मीडिया ऑडीटर,बालाघाट (निप्र)। बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में खर्रादार नदी पर बन रहे पुल के पास एक सूखे नाले से पिछ्ले चार दिनों से लापता चौकीदार बिंटु वल्के (55 वर्ष) का शव मिला है। रमगढ़ी के रहने वाले बिंटु बीते 20 जून से लापता थे और बुधवार को उनका शव काफी क्षत-विक्षत (डी-कंपोज्ड) हालत में मिला। बिरसा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि बिंटु निर्माणाधीन पुल की साइट पर बतौर चौकीदार काम करते थे। वे 20 जून की शाम को घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। घरवालों ने काफी खोजबीन करने के बाद 21 जून को बिरसा थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को पुलिस को पुलिया के पास सूखे नाले में उनका शव होने की सूचना मिली। 2-3 दिन पुराना है शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राजथाना प्रभारी के मुताबिक, शव की हालत को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है।

अकोदिया में एक रात में दो वाहनों से बैटरियां चोरी:CCTV में कैद हुए बदमाश, 50 हजार से अधिक का सामान चोरी

मीडिया ऑडीटर,अकोदिया (निप्र)। अकोदिया क्षेत्र में वाहन बैटरी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात अकोदिया-सारंगपुर रोड पर दो अलग-अलग स्थानों पर खड़े वाहनों से बैटरियां चोरी कर ली गई। दोनों घटनाओं में बदमाश सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सलसलाई स्थित देवश्री हीरो शोरूम के लोडिंग वाहन से अज्ञात बदमाश बैटरी और सेंसर बॉक्स चुराकर ले गए। शोरूम कर्मचारी नितेश मेवाड़ा ने बताया कि 23 जून की शाम वाहन को शोरूम के सामने खड़ा किया गया था। मंगलवार सुबह शोरूम पहुंचने पर बैटरी बॉक्स का ताला टूटा मिला और बैटरी व सेंसर बॉक्स गायब थे।

शोरूम के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना: घटना की जानकारी मिलने के बाद शोरूम संचालक राजेंद्र मेवाड़ा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में बदमाश वाहन से बैटरी निकालकर अपने साथ लाई गई चार पहिया गाड़ी में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

डंपर से भी दो बैटरियां ले गए चोर: इसी रात अकोदिया-सारंगपुर रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास खड़े नरेंद्र यादव के डंपर को भी निशाना बनाया गया। बदमाश डंपर से दो बैटरियां चुराकर ले गए। चोरी गई बैटरियों की कीमत 50 हजार रुपए से अधिक बताई जा रही है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है।

फर्जी नंबर प्लेट की आशंका: पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में चोरी में इस्तेमाल किया गया वाहन भोपाल पासिंग नंबर का दिखाई दे रहा है।

हालांकि जांच के दौरान संबंधित वाहन मालिक ने बताया कि घटना के समय उसकी गाड़ी घर पर खड़ी थी। इसके बाद पुलिस को फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की बात कही गई है।

सीहोर जिला जेल में कैदी की मौत:परिजनों का आरोप- प्रबंधन समय पर इलाज करवाता तो बच सकती थी जान

मीडिया ऑडीटर,सीहोर (निप्र)। सीहोर जिला जेल में बुधवार सुबह एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान श्रीराम वर्मा के रूप में हुई है, जो एक मारपीट के मामले में जेल में बंद था। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कैदी का समय पर और उचित इलाज नहीं कराया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। मामले के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप: मृतक के परिजनों का आरोप है कि श्रीराम वर्मा की तबीयत खराब थी, लेकिन जेल प्रबंधन ने उसके इलाज को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उनका कहना है कि यदि समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो उसकी जान बच सकती थी। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जेल प्रबंधन ने मीडिया से बनाई दूरी: घटना के बाद जेल प्रबंधन की ओर से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जेल अधिकारियों ने फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए रखी है, जिससे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

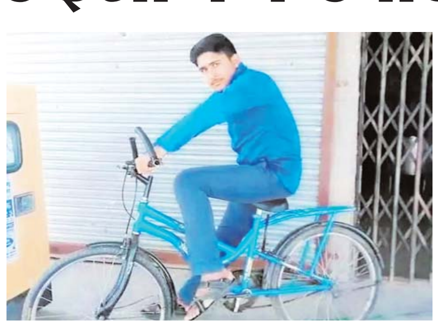

मारपीट के मामले में जेल में था बंद: जानकारी के अनुसार श्रीराम वर्मा को 26 अप्रैल की शाम हुई एक मारपीट की घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस ने उसे अन्य आरोपियों के साथ आरोपी बनाया था और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

पुराने जमीनी विवाद से शुरू हुआ था विवाद

फरियादी नेपाल वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके भाई अनूप सिंह वर्मा खेत से भागते हुए घर पहुंचे थे।

अनूप ने बताया था कि खेत पर मोटर चालू करने के दौरान गांव के मनोज वर्मा और अनार सिंह वर्मा ने पुराने जमीन विवाद को लेकर उनसे गाली-गलौज की और मारपीट करने के लिए दौड़ पड़े।

घर के बाहर बढ़ा विवाद

शिकायत के अनुसार अनूप के पीछे-पीछे मनोज वर्मा और अनार सिंह वर्मा डंडे और चाकू लेकर नेपाल वर्मा के घर तक पहुंच गए। जब नेपाल वर्मा, उनके भाई अनूप, चंदर और पिता कैलाश वर्मा बाहर आए और समझाने का प्रयास किया।

झगड़े में कई लोग हुए थे घायल

इसी दौरान श्रीराम वर्मा, सीता बाई और दुर्गाप्रसाद भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि अनार सिंह वर्मा ने चाकू से कैलाश वर्मा पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी लाठी-डंडों से हमला किया, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुए थे।

बीच-बचाव कर बचाई गई थी जान

फरियादी नेपाल वर्मा के अनुसार गांव के हरगोविन्द ठाकुर और नीरज वर्मा ने बीच-बचाव कर घायलों को बचाया था। आरोपियों ने घटना के बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दिल्ली प्रीमियर लीग: 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा तीसरा सीजन, जानिए कब होगी नीलामी

नई दिल्ली एजेंसी। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। एक महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुषों की आठ टीमें और महिलाओं की चार टीमें हिस्सा लेंगी। पिछले सीजन में, नीतीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस ने अपना पहला डीपीएल खिताब जीता था। इस टीम ने फाइनल मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से मात दी थी। महिलाओं की प्रतियोगिता में श्वेता सहरावत की अगुवाई वाली साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने फाइनल में सेंट्रल दिल्ली क्वींस को हराकर चैंपियनशिप जीती थी। आगामी सीजन में कई प्रमुख क्रिकेटर्स शामिल होंगे, जिनमें भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और आईपीएल स्टार ऋषभ पंत, इशांत शर्मा, नीतीश राणा, हर्षित राणा, नवदीप सैनी, आयुष बडोनी, अनुज रावत, प्रियांश आर्य, सुयश शर्मा, दिग्वेश राठी, मयंक रावत, प्रिंस यादव, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, हिम्मत सिंह, ऋतिक शौकीन और सार्थक रंजन जैसे नामी खिलाड़ी शामिल हैं।

महिला प्रतियोगिता में श्वेता सहरावत, प्रिया पुनिया, सोनी यादव और आयुषी सोनी जैसी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ-साथ तनीषा सिंह, नजमा, मोनिका और पूर्वा सिवाच जैसी युवा प्रतिभाओं के भी शामिल होने की उम्मीद है।

डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा, हर साल, दिल्ली प्रीमियर लीग बेहतर होती गई है। यह लीग तेजी से हमारे क्रिकेट कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। खिलाड़ियों और फैंस के बीच समान रूप से जबरदस्त रुचि पैदा की है। हमने कई क्रिकेटर्स को डीपीएल में शानदार प्रदर्शन करते और खेल के उच्चतम स्तर पर टीमों का प्रतिनिधित्व करते देखा है। यह लीग दिल्ली क्रिकेट में टैलेंट की पहचान करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गई है। हमें भरोसा है कि सीजन 3 एक बार फिर खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को अपनी काबिलियत दिखाने का मंच देगा।

मेंस दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली किंग्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, आउटर दिल्ली वॉरियर्स, पुरानी दिल्ली 6, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस की टीमें शामिल हैं, जबकि महिलाओं की प्रतियोगिता में सेंट्रल दिल्ली किंग्स विमेन, ईस्ट दिल्ली राइडर्स विमेन, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स विमेन और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स विमेन की टीमें हैं।

संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कानूनी मदद लूंगी

एशियन गेम्स के स्क्वॉड से बाहर किए जाने पर बोलीं मनिका बत्रा

नई दिल्ली एजेंसी। एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा चर्चा में हैं। मनिका ने हाल ही में टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए थे और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील भी की थी। अब उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि वह टीम में शामिल किए जाने या अपने लिए विशेष व्यवस्था की मांग कर रही हैं। मनिका ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष सुविधा या रियायत की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहती हैं। उन्होंने टीम से बाहर किए जाने के फैसले को मनमाना बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकती हैं। मनिका ने एक बयान में कहा, पिछले दो दशकों से मुझे सर्वोच्च स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। अपने पूरे करियर में मैंने जीत, हार, चयन और चयन न होने, सभी परिस्थितियों को स्वीकार किया है। यह खेल का हिस्सा है।

लेकिन जिस बात को स्वीकार करना मुश्किल है, वह है पारदर्शिता की कमी और मनमानी।

उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने कई लोगों को यह कहते हुए देखा है कि मैं एशियन गेम्स टीम में जगह चाहती हूं या विशेष विचार की मांग कर रही हूं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं चयन की मांग नहीं कर रही हूं और न ही किसी से फैसला बदलने को कह रही हूं। मैं सिर्फ जवाब मांग रही हूं। मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरा चयन क्यों नहीं किया गया। यदि मुझे इस फैसले के आधार के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो मेरे पास कानूनी विकल्प अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं यह इसलिए नहीं कर रही हूं कि मुझे टीम में जगह या कोई विशेष व्यवस्था चाहिए, बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही मिलनी चाहिए।

मनिका ने कहा कि वह करीब 20 वर्षों से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और केवल एक स्पष्ट तथा ईमानदार जवाब चाहती हैं। उन्होंने अपनी मौजूदा विश्व रैंकिंग का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब वह विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर हैं और शीर्ष-50 से मामूली अंतर से बाहर हैं, तो उन्हें चयन के योग्य क्यों नहीं माना गया।

फीफा वर्ल्ड कप: रोनाल्डो का चला जादू

पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से रौंदा

नई दिल्ली एजेंसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से रौंदा। ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए। पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी को भी मजबूत कर लिया है। टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 प्वाइंट हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा, पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी एक-एक गोल दागा। वहीं, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी नेमातोव अपना ही गोल कर बैठे। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के छठे मिनट में ही रोनाल्डो ने अपनी क्लास दिखाई और टीम के लिए पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। वह छह विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।

पुर्तगाल की बढ़त को मैच के 17वें मिनट में ही नुनो मेंडेस ने दोगुना कर दिया। नुनो ने फ्री किक का भरपूर फायदा उठाया और मैच का दूसरा और अपना पहला गोल किया। मैच के 29वें मिनट में उज्बेकिस्तान के लिए अजीजजोन गनीव ने एक शानदार गोल किया, लेकिन फाउल होने के कारण इससे अमान्य करार दे दिया गया।

इसके बाद मैच के 39वें मिनट में रोनाल्डो ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल दागा। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने पहले हाफ का अंत 3-0 की बढ़त के साथ किया।

कोलंबिया ने बनाई नॉकआउट स्टेज में जगह

डीआर कांगो को 1-0 से हराया

गुआडालाहारा एजेंसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया। ग्वाडालाहारा स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया। मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा। इससे पहले, मैच में डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने कई शानदार बचाव किए और कोलंबिया के कई शॉट्स गोल पोस्ट में जाने से रोके। पहले हाफ में कोलंबिया ने लगातार दबाव बनाया। जेम्स रोड्रिगेज, लुइस डियाज, और गुस्तावो पुएर्ता के शॉट्स को मपासी ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में तब्दील नहीं होने दिया। डेनियल मुनोज ने भी कई मौके बनाए, लेकिन शुरुआती हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। डीआर कांगो के पास भी गोल करने के कई मौके आए, लेकिन टीम इन्हें भुनाने में नाकाम रही। एडो कायम्बे का एक लंबी दूरी का शॉट बाहर चला गया। वहीं, योएन विसा का हेडर भी गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने आक्रामक खेल दिखाया और डीआर कांगो के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। लुइस डियाज ने गोल करने का शानदार मौका बनाया, लेकिन एक बार फिर डीआर कांगो के गोलकीपर मपासी उनके सामने चट्टान की तरह खड़े रहे।

डीआर कांगो के मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय पर लग रहा था कि यह मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। मैच में लुइस डियाज के दो गोल ऑफसाइड करार दिए गए, जिससे कोलंबिया की बढ़त और बड़ी नहीं हो सकी। इसके बावजूद टीम ने अपनी लीड को बनाए रखा और डीआर कांगो को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।

हॉकी इंडिया ने यूके दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम का किया ऐलान, शिलेमा चानू बनीं कप्तान

नई दिल्ली एजेंसी। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम नए मुख्य कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कुल सात मैच खेलेगी। यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है।

इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में सुधार होगा। युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज दो गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा साहू, सुप्रिया, मधु, एफ. लालबी अक्सियामी, लालनेइहपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कडू शामिल हैं।

फॉरवर्ड लाइन में सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिनपुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल, सनिका चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है।

9 दिन का यह एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के खिलाफ दो मैचों से शुरू होगा, इसके बाद लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे।

यूके दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम

- **गोलकीपर :** निधि, एंगिल हर्षा रानी मिंज
- **डिफेंडर :** पूजा साहू, सुप्रिया, मधु, एफ. लालबी अक्सियामी, लालनेइहपुई, पार्वती टोपनो
- **मिडफील्डर :** खैदेम शिलेमा चानू (कप्तान), तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद, तनुश्री दिनेश कडू
- **फॉरवर्ड्स :** सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिनपुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल, सनिका चंद्रकांत माने, कृष्णा शर्मा ।

12 करोड़ के घाटे के साथ डीसी में लौटे ऋषभ पंत

कुलदीप अगले सीजन L S G की जर्सी में दिखेंगे

मुंबई एजेंसी। आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने एक बड़ी ट्रेड को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत अब एलएसजी से डीसी में चले जाएंगे, जबकि डीसी के कुलदीप यादव अगले सीजन में एलएसजी के लिए खेलते दिखेंगे। गवर्निंग बॉडी ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पंत अब 15 करोड़ में डीसी में वापस लौटेंगे। वहीं, कुलदीप अपनी मौजूदा फीस 13.5 करोड़ रुपये पर ही एलएसजी में जा रहे हैं। आईपीएल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ट्रेड के बाद पंत 15 करोड़ की संशोधित फीस पर डीसी में वापस आएंगे। कुलदीप अपनी मौजूदा फीस 13.50 करोड़ रुपये पर एलएसजी में शामिल होंगे। ऋषभ पंत और कुलदीप यादव दोनों आईपीएल 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक साथ खेल चुके हैं। आईपीएल 2025 और 2026 के लिए पंत एलएसजी से जुड़े थे, लेकिन कुलदीप डीसी का ही हिस्सा रहे। पंत 2016 से 2024 तक डीसी का हिस्सा रहे थे। इस दौरान वह 2021 से 2024 तक टीम के कप्तान भी रहे। पंत ने 43 मैचों में डीसी की कप्तानी की, जिसमें टीम ने 23 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 20 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। डीसी के लिए 2016 से 2024 के बीच पंत ने कुल 111 मैच खेले थे।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पर गंभीर आरोप, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का दावा

नई दिल्ली एजेंसी। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल कानूनी विवाद में घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में एक महिला और उसकी मां ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि अभिषेक पोरेल ने शादी का वादा कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा उन पर मारपीट और आपराधिक धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

तीन साल तक रिश्ते में रहने का दावा: महिला का दावा है कि वह पिछले तीन वर्षों से अभिषेक पोरेल के साथ रिश्ते में थीं। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान दोनों के बीच मतभेद शुरू हुए, जिसके बाद पोरेल ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।

अभिषेक पोरेल ने आरोपों से किया इनकार: अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उनका नाम इस तरह के विवाद में घसीटा जा रहा है।

पोरेल ने कहा, मैं इस समय अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मैं इस मामले पर बात करूंगा। अभी तक पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है।

आईपीएल 2026 में सीमित मौके, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के सिर्फ चार मौके मिले, जिनमें उन्होंने 108 रन बनाए। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक भी जड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। इसके बाद बंगाल प्रो टी20 लीग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। छह मैचों में उन्होंने 275 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 94 रन रहा।

घरेलू क्रिकेट में भी मजबूत रिकॉर्ड

अभिषेक पोरेल ने 2022 में बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया था। अब तक वह 32 प्रथम श्रेणी और 23 लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम एक शतक और 12 अर्धशतक हैं, जबकि लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने दो शतक और पांच अर्धशतक लगाए हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

घुना गेहूं और परिवहन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई: सेवा सहकारी समिति चूंद एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट, प्रबंधक व प्रभारी हटाए गए

एफसीआई जांच में घुना व अमानक गेहूं की पुष्टि, दो खेप रिजेक्ट होने के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना जिले में गेहूं उपार्जन एवं परिवहन व्यवस्था में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी समिति चूंद (तिहाई) को आगामी एक वर्ष अर्थात दो उपार्जन सीजन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही समिति के प्रबंधक एवं उपार्जन केंद्र प्रभारी को सभी उपार्जन और किसान पंजीयन संबंधी कार्यों से पृथक कर दिया गया है प्रशासन की इस कार्रवाई को किसानों के हितों की रक्षा तथा उपार्जन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समिति द्वारा खरीदे गए गेहूं की गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की जांच में गंभीर खामियां उजागर हुईं। जिला उपार्जन समिति द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 23 मई को एफसीआई को भेजी गई लगभग 6807 बोरियों, यानी 3403.5 क्विंटल गेहूं की खेप में घुना एवं अमानक गुणवत्ता का गेहूं पाया गया। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने के कारण एफसीआई अधिकारियों ने पूरी खेप को अस्वीकार कर दिया इतना ही नहीं इससे पहले महाराष्ट्र भेजी गई 493 बोरियों अर्थात 246.5 क्विंटल गेहूं की खेप भी गुणवत्ता संबंधी खामियों के कारण वापस लौटा दी गई थी। लगातार दो खेपों के रिजेक्ट होने से जिले की उपार्जन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। प्रशासन का मानना है कि ऐसी घटनाओं से न केवल किसानों को नुकसान पहुंचता है बल्कि जिले और प्रदेश की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है मामला सामने आने के बाद जिला उपार्जन समिति ने सेवा सहकारी समिति चूंद (तिहाई) को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था समिति ने अपने जवाब में दावा किया कि गेहूं की गुणवत्ता का परीक्षण एफसीआई अधिकारियों एवं नागरिक आपूर्ति निगम के सर्वेयर द्वारा किया गया था तथा परिवहन से पहले सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था समिति ने यह भी कहा था कि अस्वीकृत गेहूं का अपग्रेडेशन कराया जाए और उससे संबंधित खर्च की वसूली जिम्मेदार पक्षों से की जाए हालांकि जिला उपार्जन समिति ने उपलब्ध अभिलेखों जांच प्रतिवेदनों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद समिति के जवाब को असंतोषजनक माना समिति ने निष्कर्ष निकाला कि शासन की महत्वपूर्ण किसान कल्याणकारी योजना के संचालन में निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है इसी कारण गुणवत्ता संबंधी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं इसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी समिति चूंद (तिहाई) को आगामी एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया साथ ही समिति के प्रबंधक और उपार्जन केंद्र प्रभारी को भी सभी उपार्जन एवं किसान पंजीयन संबंधी कार्यों से हटा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सर्वेयर पवन तिवारी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं प्रशासन का मानना है कि गुणवत्ता जांच प्रक्रिया में हुई चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है इस कार्रवाई के बाद जिले में गेहूं उपार्जन भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त किए जाने की संभावना है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा किसानों के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने सत्यभान सिंह पटेल, कार्यकर्ताओं में उत्साह

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा मैहर जिले में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर सत्यभान सिंह पटेल की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति की घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में हर्ष और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्यभान सिंह पटेल को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सभी ने उनके सफल, सक्रिय एवं जनहितकारी कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होगी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति से जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा की मजबूती के लिए प्रभावी कार्य किए जा सकेंगे। कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है तथा विभिन्न स्तरों पर बधाई देने का सिलसिला जारी है स्थानीय नेताओं एवं समर्थकों ने भी सत्यभान सिंह पटेल को नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की कामना की है। सभी ने विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में संगठनात्मक कार्यों को नई दिशा मिलेगी तथा पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और समर्थकों में खुशी का वातावरण बना हुआ है।

शिक्षा के नाम पर कारोबार का आरोप, निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने का दबाव, अभिभावकों में नाराजगी

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नागौद नगर स्थित एक निजी किंडरगार्टन स्कूल पर अभिभावकों से निर्धारित दुकानों से ही किताबें ड्रेस एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आवश्यक सामग्री केवल सुंदरानी ड्रेसेस एवं हैप्पी स्टेशनरी से ही खरीदी जाए, जिससे उन्हें अन्य स्थानों से खरीदारी करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है अभिभावकों के अनुसार इस व्यवस्था से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है साथ ही सामग्री की गुणवत्ता और कीमत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, एक अभिभावक ने जब स्कूल ड्रेस की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई तो विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि इसके बाद संबंधित दुकान संचालक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया जिससे मामला और गंभीर हो गया घटना के बाद मामला नागौद थाना तक पहुंचा जहां दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर समझौते के प्रयास किए गए और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की गई इसके बावजूद क्षेत्र में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूलों द्वारा इस तरह की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और अभिभावकों को राहत मिल सके।

एम.आई.सी. बैठक में शहर के समग्र विकास एवं जनहित के मुद्दों पर हुए महत्वपूर्ण निर्णय, विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने पर जोर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नगर निगम कार्यालय स्थित नमो सभागार में आज मेयर-इन-काउंसिल (एम.आई.सी.) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर के महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने की बैठक में शहर के समग्र विकास नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना तथा उन्हें और अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना रहा इस दौरान पेयजल व्यवस्था स्वच्छता सड़क सुधार, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम का प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुँचाना है उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित एवं सतत विकास के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम पूरी पारदर्शिता, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा बैठक में शहर को स्वच्छ सुंदर एवं विकसित बनाने के लिए जनसहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया गया इस अवसर पर नागरिकों से अपील की गई कि वे नगर निगम के विकास कार्यों में सहयोग करें तथा शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं इसके साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नगर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

संयुक्त बस चेकिंग अभियान जारी 37 बसों की जांच, 12 पर हुई कार्यवाही

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार सतना जिले में परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया यह अभियान माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप संचालित किया गया जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना रहा है। अभियान के दौरान कुल 37 बसों की सघन जांच की गई जांच में 12 बसों में आंशिक कमियां पाई गईं दजिन पर कार्यवाही करते हुए 12 हजार रुपये का राजस्व वसूला गया। अधिकारियों ने बस चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सुरक्षा मानकों का पालन करने की समझाइश दी। इस दौरान बसों में लगे अग्निशमन यंत्र के उपयोग को लेकर मौके पर ही डेमो दिया गया ताकि आपात स्थिति में चालक एवं स्टाफ सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें इसके अलावा स्कूल बस संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहनों में परमिट फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें। साथ ही बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, ड्राइवर एवं कंडक्टर की वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इस संयुक्त अभियान में आरटीओ रवि बरेलिया, यातायात विभाग से एएसआई मार्तण्ड सिंह, देवेंद्र चौधरी, प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सुब्बा, मनोज गौतम एवं रामसुख मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता, नागरिकों को डिजिटल ठगी से बचाव की दी जानकारी

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। जिले में पुलिस विभाग द्वारा 'सेफ क्लिक 2.0 - सुरक्षित क्लिक सुरक्षित जीवन' अभियान के अंतर्गत साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन ठगी फर्जी लिंक साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराधों एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क करना है ताकि वे सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकें अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों तथा ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान नागरिकों को समझाया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही संदिग्ध कॉल, मैसेज एवं ऑनलाइन ऑफर्स से सावधान रहने की भी सलाह दी गई पुलिस टीम ने लोगों को यह भी बताया कि साइबर ठगी होने की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या साइबर क्राइम पोर्टल पर सूचना दें जिससे समय रहते कार्रवाई संभव हो सके। अभियान के माध्यम से डिजिटल युग में सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने और साइबर अपराधों की रोकथाम का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ा है ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है अभियान के माध्यम से पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकें, जिससे एक सुरक्षित डिजिटल समाज का निर्माण हो सके।

विनोद गेलानी विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए फिर से मैदान में, व्यापारियों से समर्थन की अपील

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। रक्तदान सेवा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके, हार्डवेयर एवं पेंट एसोसिएशन में महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे तथा सक्रिय समाजसेवी एवं रक्त प्रेरक विनोद गेलानी एक बार फिर विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के आगामी चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनावी मैदान में उतर आए हैं विनोद गेलानी लंबे समय से व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने, सामाजिक सेवा कार्यों में भागीदारी तथा संगठनात्मक गतिविधियों में निरंतर योगदान के चलते वे क्षेत्र में एक सक्रिय और भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं उन्होंने कहा कि यदि उन्हें व्यापारियों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होता है तो वे विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उनका उद्देश्य व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाना, नए व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना तथा संगठन को सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना के साथ आगे ले जाना है विनोद गेलानी ने विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स को व्यापारियों की आवाज बताते हुए संगठन की मजबूती को व्यापारिक विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वे हर व्यापारी के सुख-दुख में सहभागी बनकर संगठन की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे उन्होंने चेंबर के मतदाताओं एवं व्यापारियों से समर्थन और सहयोग की अपील करते हुए विश्वास जताया कि व्यापारिक एकता और सहयोग से ही संगठन को नई दिशा मिल सकती है उनकी सामाजिक सक्रियता निरंतर सेवा कार्यों और व्यापारिक क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति के चलते व्यापारियों में उनके प्रति उत्साह और विश्वास का वातावरण देखा जा रहा है।

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आज करेंगे बस्ती और छात्रावास का औचक निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव प्रवास के तीसरे दिन 25 जून को प्रातः 10 बजे अनुसूचित जाति बस्तियों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे स्थानीय आडिटोरियम जिला पंचायत के सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग से सामाजिक संवाद तथा सामाजिक एवं धार्मिक बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा दोपहर 2 बजे अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण करने के पश्चात दोपहर 3 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

पैरा कमांडो में चयनित होकर जयप्रकाश ने मझगवां का नाम किया रोशन, नगर में हर्ष का माहौल

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। होनहार युवा जयप्रकाश गुप्ता ने पैरा स्पेशल कमांडो में चयनित होकर मझगवां क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। जयप्रकाश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गायत्री चौक मझगवां स्थित अपने ननिहाल में रहते हुए पूरी की। वे अपने नाना जगपत लाल गुप्ता के संरक्षण में रहे, जहां मिले संस्कारों और उचित मार्गदर्शन ने उनके जीवन को नई दिशा दी जयप्रकाश ने कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास के बल पर अग्निवीर में चयन प्राप्त किया और उसके बाद पैरा स्पेशल कमांडो का टेस्ट एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर अपनी योग्यता, दक्षता और क्षमता का उत्कृष्ट परिचय दिया उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है इस सफलता के साथ ही जयप्रकाश ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे मझगवां नगर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया है जयप्रकाश गुप्ता की इस सफलता पर नगर के युवा व्यवसायी रोशन अग्रवाल, कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी, शिक्षक पंकज कपूर, अजय पाण्डेय, आशीष पांडेय, गोविंद सिंह पिंडरा, के.के. गौतम, बबलू गुप्ता सहित अनेक नागरिकों ने उन्हें एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी है समस्त नगरवासियों ने उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जयप्रकाश की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

अनुसूचित जाति कल्याण कार्यों में तेजी लाएं, छात्रावासों की व्यवस्थाएं बेहतर करें : डॉ. कैलाश जाटव

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. कैलाश जाटव ने सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी विकास योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और प्रभावी रूप से पहुंचे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बैठक में कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम राहुल सिलाडिया, एलआर जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते, जिला संयोजक जनजातीय कार्य डॉ. अरुण शुक्ला, एलडीएम गौतम शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह, जिला पंजीयक डॉ. कीर्ति सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे बैठक में डॉ. जाटव ने अनुसूचित जाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर कहा कि सभी सीटों पर पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए छात्रावासों में रहने, भोजन, साफ-सफाई, प्रकाश एवं पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से छात्रावासों का प्रत्येक माह नियमित निरीक्षण कराया जाए और निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों को तत्काल दूर किया जाए। अध्यक्ष डॉ. जाटव ने शिक्षा के क्षेत्र में निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल एवं कॉलेजों में प्रवेश लेने के बाद अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र तत्काल भरवाए जाएं, ताकि कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे इसके साथ ही छात्रावासों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गएआयोग के अध्यक्ष डॉ. जाटव ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया कि स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को भेजे गए प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए तथा अनुसूचित जाति हितग्राहियों को सहानुभूतिपूर्वक ऋण एवं अनुदान वितरित किया जाए। स्वरोजगार के प्रकरणों को केवल उचित कारण होने पर ही निरस्त किया जाए बैठक में उन्होंने जिला संयोजक को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों का सर्वेक्षण कराया जाए और जहां आवश्यक हो वहां पेयजल एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं इसके लिए जिला खनिज मद एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाए अधिकारियों द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति हितग्राहियों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा निःशुल्क पुस्तकें मध्यान्ह भोजन एवं गणवेश उपलब्ध कराए जा रहे हैं अध्यक्ष डॉ. जाटव ने जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए सीएम हेल्पलाइन में अनुसूचित जाति कल्याण से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने को कहा।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।